साप्ताहिक समय माया

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

पंजीयन क्रमांक RNINDPM\HIN\16730/12/1/97/TC

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Tel : 91-731-2102725
Cell : 91-9827330697
Fax : 91-731-2531630
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/corruption2india/ eduIndore.html
www.geocities.com/corruption2india/ corruptindia.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com

वर्ष 6 अंक 32 इन्दौर, जबलपुर सोमवार, 8 से 14 नवंबर 2004 पृष्ठ 8 मूल्य रु.2/-

2 **संपादकीय** पुलिस शासकीय अपराधियों का गिरोह

3 पंजीयन विभाग भ्रष्टाचारियों का अड्डा

4 वोटों की राजनीति, नियोक्ता को कटोरा थामने के लिए मजबूर कर देगी

5 भ्रष्ट विभागों में अचानक छापे क्यों नहीं पड़ते

7 परिवहन विभाग में अवैध वसूली पर गिरी गाज

8 भ्रष्ट सेवक नहीं, अप्रेन के गिद्धों के नर्सिंग या डेथ होम्स

पृथ्वी की यात्रा पथ पर दीपावली के दीप सुख-समृद्धि से प्रकाशित करें

जनता अमेरिका की भी बिहार जैसी ही....

बुश, लालू जैसा अपराधी पुन: अमेरिकी राष्ट्रपति

दुनिया जिस अमेरिका और अमेरिका की जनता को महान मानती है बुश के चुनाव जीत कर सत्ता में वापिस लौटने ने सिद्ध कर दिया कि कदापि ऐसा नहीं जैसे भारत में बिहार की जनता है वही औकात अमेरिकियों ने दिखाई।

दुनिया में जनता कहीं की भी हो, मानसिकता लगभग एक जैसी है। बुश की बदतमीजियों, लालच, वृहद नरसंहार, राष्ट्र विरोधियों से हाथ मिलाकर चुनाव जीतने, राष्ट्र में बेरोजगारी बढ़ाकर, पूंजीपतियों, संयुक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कठपुतली बन नाचने और अमेरिकियों को अफगानी युद्ध और ईराकी युद्ध में झोंककर मरवा डालने का आरोपी होने के बाद भी उसे चुन लिया जाना बताता है कि अमेरिकी जनता भी बिहारी जनता से ज्यादा कुछ भी नहीं।

जनता को स्वयं ज्यादा प्रगतिशील अच्छे नेता नहीं लुभाते। उन्हें लालू बुश जैसा जालसाज, हत्यारे, लुटेरे ही भाते हैं। भारत की जनता को अटल जैसे प्रगतिशील, अच्छे नेता पसंद नहीं आते। उन्हें कांग्रेसी जालसाज लुटेरे और भ्रष्ट ही पसंद आते हैं।

हाल ही में संपन्न हुए अमेरिकी चुनावों में बुश की जीत ने सिद्ध कर दिया कि जनता चाहे बिहार की हो या अमेरिका की सब एक जैसी ही होती है। जिस पर दुनिया थूक रही थी अमेरिकियों ने उसे चाट लिया। जहां तक अमेरिकियों का सवाल है तो अमेरिका दुनिया की सारी मानव समाज की संकर प्रजाति से उत्पन्न लोगो का वह देश है जहां मक्कार, चालाक गिद्धों का बोलबाला है। जो दुनिया में निकृष्टतम हैं, पर अपने आपको महान समझते हैं। स्वाभाविक है उन्हें वैसा ही राष्ट्रपति पसंद आएगा जिसे उन्होंने हाल ही में चुना।

लालू जैसा जालसाज गिद्ध, डकैत, वृहत जन संहारों, अरबों रुपए की जालसाजी, अपहरण, लूट, हत्याकांडों का दोषी ही पिछले 15 वर्षों से बिहार की सत्ता में येन-केन-प्रकारेण बैठा है।

बुश जिसने पिछले 4 वर्षों में अमेरिकी संयुक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कठपुतली बन उनके इशारे पर नाच रहा है। 11 सितंबर की घटना के पीछे जैसा कि फ्रांसीसी पत्रकारों ने लिखा अमेरिकी अपनी रणनीति का आंतरिक परिणाम थी। ओसामा बिन लादेन के कंधों पर बंदूक रख कर पहले अफगानिस्तान को बर्बाद कर उस पर कब्जा जमा कर दक्षिणी एशिया में उसने अपना रुस, भारत, ईरान और पाकिस्तान के बीच अड्डा जमा कर पूर्णत: इन चारों देशों पर निगाह रखने के लिए किया। उसे ओसामा को न तब पकड़ना था न अब पकड़ना है। उसे तो उसकी आड़ लेकर अपनी रणनीति को स्थापित करना था उसने कर लिया।

वही हाल ईराक में किया। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश पर कब्जा कर दुनिया के अन्य देशों को चलते पहियों कीधुरी जो पेट्रोल से चलती है पर कब्जा जमा कर उससे लाभ कमाना और दुनिया के अन्य दुश्मन देशों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाकर उन्हें भिखारी बना अपने सामने कुत्तों की तरह पूंछ हिलाते देखना चाहता था जो उसने हाल ही चुनावों की आड़ लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की कीमतों को अमेरिकी डालर 55 से 57 तक पहुंचाकर देख लिया।

(शेष पेज 6 पर)

शत्रु तांडव करें-सत्ताधीश मजे

पूर्वोत्तर में बढ़ती हिंसा, मरती जनता, आतंकी पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका चारों तरफ से घुसपैठ कर आतंकवाद फैला रहे हैं और सत्ताधीशों को विदेश यात्राओं और मौजमस्ती से फुर्सत नहीं।

अमेरिका समर्थित पाकिस्तान की आई.एस.आई की घुसपैठ में चीन सक्रिय साझेदार है। नेपाल की ढीली और भ्रष्ट राजशाही लोकतंत्र की षड्यंत्रकारी प्रबंधन के कारण आतंकवादियों, तस्करों का वह न केवल पाकिस्तानी, चीनी, षड्यंत्रकारियों, जासूसों, आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है, वरन वे नेपाल में बैठकर पूर्वोत्तर राज्यों, असम, मेघालय, नागालैंड में न केवल बम विस्फोटों, हिंसा का तांडव कर निरीह जनता को मार रहे हैं, वरन अपने स्थायी कैंपों में से आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं।

वही हाल बांग्लादेश का भी हो रहा है, जिसे हमने आजाद करवाया था अब वह आई.एस.आई. की गतिविधियों का न केवल अड्डा बन चुका है, जो न केवल पूर्वोत्तर राज्यों, वरन उत्तरप्रदेश, बिहार में उसके आतंकवादा, षड्यंत्रकारी वहां के स्थायी निवासी बनकर वर्षों से रह रहे हैं।

वही हाल श्रीलंका का है। वहां से भी लिट्टे दक्षिण भारत में बैठे नक्सलियों पीपुल्स वार ग्रुप के लोगों को प्रशिक्षण और हथियार भी दे रहा है। हम प्रत्यक्ष और परोक्ष शत्रुओं से घिर रहे हैं। परन्तु सत्ताधीश क्या मनमोहन और क्या सोनिया व उनकी गैंग अपने छह वर्ष के विपक्ष में बैठ कर जेब का खाने से बैंक-बैलेंस की कसर पूरी करने जुटी है।

कांग्रेस के समय में ही क्यों सक्रिय होते हैं। चारों तरफ के आतंकवादी, क्यों बढ़ जाता है दिन दूना रात चौगुना भ्रष्टाचार। फिर वह चाहे भारत संचार निगम हो, पोस्ट ऑफिस, आयकर, सेन्ट्रल एक्साइज, रेलवे, पासपोर्ट कार्यालय, विदेशी विभागों से देशी गृह विभाग व अन्य सभी विभागों में निगमों, निकायों में क्यों कि वो भ्रष्ट, लुटेरे कांग्रेसियो की गैंग सत्ता सुख में डूब जाती है। उसकी बला से जनता कल की भरती आज भरे।

पूरे देश में चारों तरफ आतंकवाद पैर पसार रहा है। उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 26 आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जिन्हें पाकिस्तान की आई.एस.आई. प्रशिक्षण देती है तो चीन हथियार, गोला-बारूद जिससे वारदात करे। फिर नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार की सीमा में भाग जाएं। नि:संदेह अमेरिका वित्त पोषित भिखारी पाकिस्तान आई.एस.आई. की सरकारी एजेंसी हैं, उसके सारे दिखावे आतंकवादी संगठनो को प्रतिबंधित करने और गिरफ्तार करने के केवल झूठे दिखावे हैं। फिर सच्चाई ये है कि आई.एस.आई. पाकिस्तान शासन की समर्थित पोषित संगठन है जो कम से कम भारत के लिए घोर शत्रुता के साथ पूरे देश के हर शहर में अपना जाल फैला चुका है, जिसे न केवल कांग्रेस, सपा, बसपा, लालू की पार्टी और लालू का खुला समर्थन न केवल प्राप्त है। वरन ढेर सारे आई.एस.आई. के एजेंट इन पार्टियों के नेता बन बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में व्यवसायी बन हवाला कांडों के माध्यम से इन आतंकवादी संगठनों को धन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। जाली मुद्रा देश में खफा रहे हैं, जिसके प्रमाण न केवल दिल्ली मुंबई, कश्मीर में पिछले सन 1975 के बाद से मिलते रहे हैं। कांग्रेसी गिद्धों की परंपरा रही है, उन्हें सत्ता चाहिए आतंकवाद से, दहशत फैलाकर कांटों को बमों से उड़ाकर या विपक्षी राजनीतिज्ञों बमों की राहों में कांटे बिछाकर, सत्ता मिटते ही वो हरामखोर सत्ता सुख भोगने, विदेश यात्राएं करने, विदेशों में अय्याशियां करने, बैंक बैलेंस बढ़ाने, संपत्तियां खरीदने में जुटे रहते हैं। फिर वह पैसा चाहे आई.एस.आई. से आए, अपराधियों से आए, स्थानांतरण से, आतंकवादी से, शासन के धन की लूटपाट से, जनता के धन से, अवैध वसूली से आए, भाजपा में नि:संदेह कमाई करने वाले भी थे, परन्तु राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से धन लेने के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए। जबकि कांग्रेसियों में भ्रष्टाचार का तो कदम-कदम पर बोलबाला है। आर.आर. ख़ान देश का जाना-माना कुख्यात तस्कर, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कांग्रेस का रतलाम का विपक्ष का नेता था। रु. 1 करोड़ की हेराफेरी करने में उसकी हत्या कर दी गई। अब मेहमूद खान है। वह भी हथियार कांड का सरगना था, पर कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेसियो का इतिहास कुकर्मों का इतिहास रहा है। उसकी बला से कल का टूटता देश आज टूटे। चाहे कश्मीर, असम, मेघालय, सिक्किम जाए उसको तो सत्ता सुख भोगने और अपनी अय्याशियों से मतलब रहा है।

(शेष पेज 6 पर)

नई बोतल में पुरानी शराब काम के बदले अनाज

अटल शासन के दौरान प्रारंभ की गई प्रधान मंत्री रोजगार योजना में ग्रामीणों के ग्रामों से पलायन रोकने, अतिरिक्त कार्य दिवस उपलब्ध करवाकर ग्रामीणों को रोजगार देने और रोजगार और कार्य के बदले चूंकि धन में भ्रष्टाचार होता है और धन पूरा नहीं मिल पाता इस दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को सीधा गेंहू, चावल देने की जो योजना तैयार की थी जो पूरे देश में जिलाधीश के माध्यम से जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारी को क्रियान्वयन करवाना होता है।

हाल ही में वर्तमान प्रधान मंत्री मनमोहन ने उसी योजना का नाम

बदलकर काम के बदले अन्न योजना देकर अपने आप को लोकप्रिय बनाने और जनता से जुड़ने की नौटंकी करते हुए इसी योजना जवाहर लाल नेहरू की 115वीं जयंति के उपलक्ष्य में आंध्रप्रदेश के आदिलाबाद से शुरू किया। अर्थात योजना पिछले 4 वर्षों से चल ही रही है, परन्तु अपनी नौटंकी दिखाने और प्रचार माध्यमों में छाये रहने के लिए इसी योजना का उद्घाटन आंध्रप्रदेश से शुरू कर ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार देने का शिगूफा छोड़ा गया। इसके विपरीत इस योजना की सच्चाई यह है कि इस योजना का अधिकांश गेंहू भारतीय खाद्य निगम से

(शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक
समय माया

सम्पादकीय

सत्ता की मलाई चटोरों का राजनीति दल-दल

प्रजातंत्र में वर्तमा में राजनीतिक दल नहीं वरन गिरोह बन गए हैं। चाहे भाजपा कांग्रेस या अन्य कई राजनीतिक दल नहीं, दलदल बन चुके हैं। जिनका एक मात्र उ-ेश्य है कहीं से, कैसे भी सत्ता के गलियारे में पहुंच कर जनता के धन, उससे प्राप्त सुख, सुविधाएं, प्राप्त शक्ति कादुरुपयोग कर येन-केन-प्रकारेण सबका दोहन कर धन संग्रहण कर अपने उचित अनुचित उ-ेश्यों की प्राप्ति करना रह गया है।

चाहे वो पंच, सरपंच, पार्षद, महापौर विधायक का उम्मीदवार येन-केन-प्रकारेण बिना मेहनत करे, माता-पिता, काका, दादा के नाम पर बन कर सत्ता के गलियारों में घुस कर जनता के धन को उनकी सुख सुविधाओं के नाम पर खुद हड़प सके। अब राजनीतिक दल नहीं अपराधियों, गिरोहों बन चुके हैं जो सत्ता में पद प्राप्त कर शांति, संपन्न हो अधिकारों का दुरुपयोग कर एक तरफ जनता से तो दूसरी तरफ जनता से करों के माध्यम से वसूले गए धन को डकार सकें। फिर चाहो वो उनके स्वास्थ्य के नाम पर शिक्षा, साफ सफाई, सड़कों, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को देने के नाम पर ही क्यों न हो।

अपनी लूट-खसोट के माध्यम से जनता के धन को अपनी प्रेमिकाओं पर लुटाए उनके नाम से बड़े-बड़े उद्यान बनाए, कंप्यूटर सेंटर बनवाएं, धर्म के नाम के पैसे को अधर्म पर खर्च करे। ऐसे हरामखोर अपराधियों की जब पत्रकार सच्चाई जनता के सामने रखें तो वे श्वानों का गिरोह काटने को दौड़े।

अब राजनीति में हत्यारे, लुटेरों, सट्टा जुए के अड्डे चलाने वाले, चोरी डकैती, वैश्यावृत्ति के अड्डे चलाने वाले, अवैध जमीनों की हड़पकर कालोनी काटने वालों, भ्रष्टाचारी समाज का कल्याण करने की कसमें खाने वाले अपराधियों को कानून से बचने जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए राजनीति की शरण लेकर अधिकार संपन्न हो जाने वाले गिरोहों का दलदल बन चुका है। अब राज करने की नीति ऐसे गिरोह बाजों के हाथों में है।

फिर जनता के सामने स्वच्छ छवि वाले तो दूर-दूर तक नजर नहीं आते। उनके सामने विकल्प होता है कौन कम बुरा, कम अपराधी, कम अपराधियों का गिरोह है। उसकी आपराधिक मानसिकता कितने छोटे अपराध करने की है वो ऐसे छोटे अपराधी को मजबूरी में सत्ता की तरफ धकेलती है। क्योंकि वह जिस भी दल से खड़ा या उम्मीदवार बनाया गया है उसके अपराध किस स्तर के हैं। स्वाभाविक है बड़े अपराधियों को सत्ता सौंप वह अपनी परेशानियों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहती जो आने वाले कल में उनके सीने पर मूंग दले और दूसरी तरफ सत्ता में बैठ कर उनकी सुविधाओं के नाम पर प्राप्त धन की मलाई स्वयं चाट कर उनके सिर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वैध-अवैध वसूली की गाज गिरे।

राजनीति आदिकाल से ही वैश्या कही जाती रही है, जिसका कोई नियम कानून नहीं। उसके कार्यकर्ता अब जनता की सेवा के उ-ेश्य से नहीं केवल सत्ता में सत्ताधारी या विपक्षी बन कर भी मौके की तलाश में गिद्ध निगाह रखकर जनता से जनता को, जनता का धन नोंचने-खसोटने वालों का गिरोह का दलदल बन चुका है। यह इंदौर म.प्र. भारत की नहीं वरन वैश्विक वर्तमान है प्रजातंत्र का।

दीपावली एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
सुप्रीम ऑटो सर्विस
7, निरंजनपुर, देवास नाका, इंदौर

पुलिस शासकीय अपराधियों का गिरोह

खाकी वर्दी पहन कर अधिकारी भी बन जाते हैं दरिंदे

शासन की खादी वर्दी पहनकर किसी के घर में घुसकर, जिसके साथ मन में आए रंगरेलियां करें, पैसा खाकर फरियादी महिला के गुप्तांग में डंडा घुसेंडे, मंदिर से मूर्तियां गायब कर सोने की हीरे लगी मूर्ति, पीतल की बना दी जाए। थाने के सामने ही पुलिस धन लेकर सट्टे, जुए के अड्डे चलवाए, वैश्यावृत्ति करवाए, गांजा, भांग, अफीम की तस्करी करवाए, डकैत सरेआम गोलियां बरसाएं, ये हरामखोर देखते ताकते रहे कि किस महिला के पूरे कपड़ों से शरीर का कौनसा खूबसूरत हिस्सा दिख रहा है, पुलिस की गाड़ियां सरेआम यातायात के नियम तोड़े, अपराधियों की शह पर फरियादी को ही थाने में बंद करें। इनके कुकर्मों की पोल न खुल जाए, इसलिए थाने में आए लोगों को गोली से भून दे। चोरी, लूट, वारदातों, वैश्यावृत्ति करने वालों, जुए सट्टे के अड्डों से खुलेआम ड्यूटी का बहाना बनाकर वसूली करते रहे। पूरे भारत में अभी तक ये सब बिहार, उत्तरप्रदेश की पुलिस ही करती रही, परन्तु म.प्र. फिर इंदौर की पुलिस कैसे पीचे रह सकती है। वर्तमान में ऐसी घटना में पुलिस की दरिंदगी, वहशीपन, सट्टे, जुए, वैश्यावृत्ति के अड्डों से खाकी वर्दी काटैक्स वसूलते रहे। बता मुख्यमंत्री बाबूलाल तेरी नपुसंकता का यही भ्रष्टाचार का प्रसाद है जनता को। जब जनता में हल्ला मचे तो उन्हीं हरामखोर लुटेरे पुलिसियों में से कुछ को जांच सौंप कर उनके कुकर्मों को फाइलों में दफन कर दिया जाए।

इंदौर। खाकी वर्दी पहनते ही मस्तिष्क अपने आप को साधारण जनता के बीच से उठकर, कानून का रखवाले कानूनों की आड़ में धज्जियां उधेड़कर जनता को तन, मन, धन सेलूटने का अधिकारी हो जाता है। फिर वो योनि गुदा या मुंह में डंडा घुसेडे या करंट लगाए, गर्म लाल लोहे की राह से सब उनको करने का अधिकार वर्दी पहन कर ही मिल जाता है। ऊपर से फिर अगर महिला पुलिसकर्मी हैं तो कहने ही क्या उसे तो औरतों को वस्त्रहीन कर नीलाम करने, करवाने, वैश्यावृत्ति करने, करवाने के लिए भर्ती किया गया था। यह तो मामला चूंकि सीमा अग्रवाल का था वो समाज में दम-खम रखती थी इसलिए ये सारे दुष्कृत्य सामने भी आ गए अन्यथा विनीत जैन ही क्या महिला थाने में लाने के बाद सामूहिक वेश्यावृत्ति करने में पुलिसियों सिपाही से लेकर एसपी, डी.एस.पी. भी पीछे नहीं रहते। महिलाओं के साथ सारे सामूहिक दुष्कृत्यों, यौन प्रताड़ना से लेकर मुख, गुदा, मैथुन तक सब किया जाता है। हर पुलिसिया वर्दी धारण करने वाला इन सबका आदतन अपराधी होता है।

खजराने थाने में हुई रघुवंशी की हत्या के पीछे भी यही कारण था कि वो अय्याश राजेन्द्र रघुवंशी श्यामलाल की लड़की के साथ दुष्कृत्य करके घर से निकला कि श्यामलाल ने देख लिया। बाद में नोंक-झोंक में श्यामलाल ने पास में पड़े हथियार से उसकी हत्या कर दी। डर और दहशत में जाकर वो थाने में खड़ा हो गया। उसको गिरफ्तार करने और कानूनी कार्रवाही करने की अपेक्षा उसकी पत्नी के सामने ही तड़ातड़ गोलियों से उसको वहीं मार डाला गया। बाद में उसे सूनसान की तरफ ले जाकर फिर गोलियां बरसाकर नई कहानी लिख दी गई कि वह नामी गुंडा था। उसके विरुद्ध अनेकों शिकायतें थीं। जबकि सच्चाई बिल्कुल विपरीत यह थी कि खजराने के अय्याश पुलिसकर्मी लड़की के साथ दुष्कृत्य करने के बाद कपड़े पहनता हुआ बाहर निकला जहां उसके पिता श्यामलाल ने तात्कालिक आवेश में आकर आन-फानन हत्या कर बैठा। हरामखोर पुलिसियों की पोल न खुल जाए इसलिए श्यामलाल को निपटाया गया। जहां तक मीडिया के भांडों का सवाल है तो सभी दैनिक के भांडों को हर थाने से मासिक लिफाफे मिलते हैं। इसलिए ये बिके हुए भांडों की फौज कभी सच नहीं लिख पाती। और ये वर्दी की आड़ में नोटों के झाड़ खड़े करके अपराधियों को पालते हैं, जनता को परेशान करते हैं। इसघटना के बाद ही आई.जी. पांडे ने पुलिसकर्मियों को किसी पर भी गोली चलाने से मना कर दिया था। इन हरामखोरों को नया बहाना मिल गया इनके सामने डकैत गोलियां बरसाते रहे और ये मूक दर्शक बन उसे फिल्मी तमाशा समझ देखते रहे तब इनकी बंदूकों में जंग लग गया था और गोलियों का बारूद चिर निद्रा में था।

थाने के आमने-सामने वैश्यालय, जुआ घर और सट्टेबाज अपना हुनर दिखाते हैं तो क्यों न दिखाएं आखिर इंदौर पुलिस को सारे शहर के सटोरियों से लगभग रु. 5 करोड़ की जो आमदनी होती है क्या उसके हिस्सेदार एस.पी. आई.जी. से लेकर गृह और मुख्यमंत्री नहीं होते। जहां तक वेश्याओं का सवाल है तो भाजपा को आए सत्ता में ज्यादा समय नहीं गुजरा है। उसके पहले तो ये ही पुलिस वाले ही पुलिस अधिकारियों से लेकर शासन में बैठे सचिवों प्रधान सचिवों, मंत्रियों तक इन वेश्याओं की आपूर्ति करते थे तो स्वाभाविक है कि ऐसी होटलों को, चकला घरों को शासकीय संरक्षण देकर रु. 2-5 करोड़ प्रतिमाह की आय शहर के थानों को होगी।

पुलिस की वर्दी का मतलब ही है शासकीय गुडों की फौज जो पैसों और प्रशासन के इशारे पर ही काम करने बैठी है। रहा सवाल मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का प्रशासन तो वैसे भी डींगे हांकने और लंबी-चौड़ी फांकने की बजाय जरा गिरेबां में झांक कर देखे कि न केवल पुलिस वरन हर शासकीय विभाग में भ्रष्टों, लुटेरों का तांडव मचा हुआ है। गौर फरमा रहे हैं कि भारी बदलाव आया है। यदि थानों में और पुलिस की नाम पट्टिका में जैसा कि आडवाणी ने कहा था कि चिप लगाकर सके हर कुकर्म पर नजर रखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जो जहां बैठा है कैसे तांडव कर रहा है।

दीपावली एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
डायमंड गैरिज
10, निरंजनपुर, इंदौर
LinkAd.Age

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
ऑल इण्डियन ट्रेडिंग कंपनी
281-82, एम.जी. रोड, इन्दौर

दीपावली एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
रामसिंग एंड संस
अंबवकुंआ, इन्दौर

दीपावली एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
रामगोपाल मंगल
60, जवाहरमार्ग, इन्दौर

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।।
(सब सुखी रहें, सब निरोग रहें)
उत्कृष्टता ही है सम्मान की सीढ़ी
हमारे सम्मानीय ग्राहको एवं डीलर्स को धन्यवाद, जिन्होंने रामा फास्फेट्स को द्वितीय कंज्यूमर पैक अवार्ड दिलवाया।
श्रेष्ठ स्वास्थ्य की कामना पर आधारित सुफला के उत्कृष्ट श्रेणी के उत्पाद अत्याधुनिक तकनीक से सभी सावधानियों का निर्वाह कर बनाए जाते हैं। शुद्धता में अद्वितीय सुफला का उ-ेश्य भोजन में स्वाद लाने के साथ ही अनुपम गुणवत्ता भी है सबके सुमंगल को समर्पित

सुफला शुद्धता का आधार, गुणवत्ता का संसार
Manufacturer: Decake, Sufla Refined Oil, Sufla Mustard Oil Sufla salt, Dr. White Detergent Powder, Sufla Groundnut oil
SUFLA
रामा फॉस्फेट लिमिटेड
रामा हाउस 4, साकेत नगर, इंदौर 452 001
फोन-2583368, 2 583392
Email: ramaind@bom4.vsnl.net.in,
LinkAd.Age

पंजीयन विभाग भ्रष्टाचारियों का अड्डा

श्रीवास्तव और भदौरिया दे रहे शासन को करोड़ों की चोट

इंदौर जिला मुद्रांक व संपत्ति के क्रय-विक्रय पंजीयन कार्यालय में प्रतिदिन की मुद्रांकों की कम खरीदी, मकानों, दुकानों, फैक्ट्रियों, गोडाउन बहु मंजिला भवनों, कार्यालयों, व्यावसायिक स्थलों का पंजीयन, प्लाटों, रहवासी क्षेत्रों आदि के रूप में कर शासन को प्रतिवर्ष करोड़ों की चोट मोहनलाल श्रीवास्तव और के. भदौरिया ही लगा देते हैं।

जिला पंजीयक को चूंकि रु. 5 लाख प्रतिमाह श्रीवास्तव द्वारा देने की जानकारी विश्वसनिय सूत्रों ने दी है। यही कारण है कि इंदौर मुख्यालय और स्वयं के कार्यक्षेत्र के क्रय-विक्रय के पंजीयन का कार्य पिछले 5-6 वर्षों से जमे श्रीवास्तव द्वारा ही किया जा रहा है, जो हर संपत्ति के क्रय-विक्रय का 1 प्रतिशत ऊपर से अपने लिए वसूलते हैं। इसके अतिरिक्त चोरी किए जाने वाले पंजीयन शुल्क का 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत मुद्रांकों में वसूलते हैं, जिसमें भास्कर हिस्सेदार होता है।

के. भदौरिया जो पंजीयन करता है ये हरामखोर चुपचाप पूरा डकार लेता है। अपने कुकर्मों के खुलने के डर से अपने पास कोई रजिस्ट्रार मोहर्रिर नहीं रखता है।

इंदौर। पूरे शहर में भू-माफियाओं को जो जाल फैला हुआ है। इस पूरे जाल का मुख्य संरक्षक होता है जिला पंजीयक। शासन की जमीनों, नजूल की जमीनों, ग्रीन बेल्ट, पार्क, सड़क, कृषि भूमि, दूसरे की जमीनों, वनों, व्यावसायिक भवनों, फैक्ट्रियों, दुकानों, गोडाउन की फर्जी रजिस्ट्रियों में ये सारे भ्रष्ट शूकरों की फौज भारी लेन-देन कर सारे ऐसे फर्जी कांडों को अंजाम देती है।

नकली करोड़ो रुपयों के मुद्रांकों के असली जालसाज नायक तो पूर्व का अपूरिया था जो अब उज्जैन में बैठा है। नकली मुद्राकों के क्रय-विक्रय में यहां 1998 से बैठे एम.एल. श्रीवास्तव ने भी भारी भूमिका निभाई थी, जो अभी तक इंदौर में बेदाग बैठा है। ये नकली मुंद्रांकों को न केवल इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर, भोपाल, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर, रतलाम तक में अर्थात पूरे पश्चिमी और मध्य के म.प्र. राज्य के जिलों में करोड़ों रुपए के मुद्रांक 1998 से सन 2002 तक इसी हरामखोर के संरक्षण में क्रय-विक्रय हुए।

उस कांड के खुलने के बाद ऐसा नहीं कि जालसाजियां होना बंद हो गई हैं। नि:संदेह जिला पंजीयक तोमर की मासिक आय इन जालसाजी कांड से रु. 10 लाख तक होती है, जिसमें श्रीवास्तव का रु. 5 लाख का हिस्सा होता है। बाद में के. भदौरिया और 7 अन्य का हिस्सा होता है। यही कारण है कि शहर में 502 से ज्यादा कालोनियों में से 350 से ज्यादा अवैध हैं। इसके बाद भी इन कालोनियों में धड़ल्ले से प्लाटों की खरीदी-बिक्री चल रही है, तो मात्र मुख्त्यार नामे के आधार पर अधिकांश कालोनियां बसी हैं, उनका वर्षों बाद भी रहवासी या व्यावसायिक भूमि में परिवर्तन नहीं हुआ है। इस जमीनों और संपत्तियों के कालोनी बनाने और काटने वालों में शहर के कांग्रेस के अगर सैंकड़ों नेता हैं, तो भाजपा के भी आधे सैंकड़ों से ज्यादा नेता इसी धंधे से अरबपति बने बैठे हैं। अधिकांश दूसरों की कृषि भूमि, रहवासी भूमि, नजूल, सरकारी भूमि, बगीचे और हरित क्षेत्र की भूमि परमुफ्त की जमीन को तृतीय पक्षकार से मुख्त्यार नामे पर लेकर पूरी कालोनी बना कर करोड़ों रुपए हड़प कर चुके हैं। इन सबके पंजीयन, क्रय-विक्रय में इस पंजीयन विभाग के भ्रष्ट सूकरों ने करोड़ों कमाकर सब काला पीला कर रखा है।

यही कारण है कि इस विभाग का पूर्णत: कम्प्यूटराइजेशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन होने से सारे कुकर्मों की पोल पट्टियां झटके से सामने आ जाएंगी, जिससे ये श्वानों की फौज कमाई नहीं कर सकेगी। शासन को करोड़ों के मुद्रांक शुल्क की चोट देकर वे यहां बैठे जिला पंजीयक तोमर से लेकर 8 अन्य उप पंजीयक और उन सबके रजिस्ट्रार मोहर्रिर क्या-क्या कुकर्म नहीं कर रहे हैं। अब जबकि शासन ने संपत्ति के फोटो लगवाने शुरू कर दिए हैं। भ्रष्ट श्रीवास्तव का पंजीयन मोहर्रिर अय्याश भास्कर और जादौन उप पंजीयक का पंजीयन मोहर्रिर गाड़वे दोनों मामा-भांजे हैं। अच्छी खासी फैक्ट्री, हुमंजिला भवनों, दुकानों, गोडाउन, मकान, भवनों, कृषि सिचिंति भूमि का ये कम कीमत के मुद्रांक लगाने के लिए फोटो लगाने के नाम पर प्लाटों, झोपड़ियों, कृषि सिंचित भूमि का, सूखी पड़ी जमीन का फोटो लगाकर पंजीयन करवा देते हैं। जिससे क्रेता विक्रेता को लाखों की बचत हो जाती है। कुल बचत का 25 से 40 प्रतिशत ये दोनों मामा-भांजे भास्कर और गाड़वे लेकर आधा अपने उप पंजीयक अर्थात भास्कर श्रीवास्तव को और गाड़वे जादौन को 12.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक देकर दोनों हाथ से कमाई कर रहे हैं। इससे शासन को प्रतिदिन न्यूनतम रु. 10 लाख से रु. 50 लाख के मुद्रांक शुल्क चोरी से घाटा हो रहा है।

संभवत: ये आंकड़ा रु. 1 करोड़ को पार कर जाता हो किसी भी दिन बगदले में वहां कार्य कर रहे उपपंजीयकों की जेब में जाता है। लाखों रुपए प्रतिदिन इस कार्य में वहां कार्यरत महिला-पुरुष, वकील अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। कुछ सुंदरियों का भी जाल बिछा है जो उल्टी-सीधी संपत्तियों की सर्च रिपोर्ट देकर उन संपत्तियों का ऊंची दरों पर मूल्यांकन करवा कर लाखों रुपए की वित्तीय ऋण सुविधाएं विभिन्न बैंकों से प्राप्त कर रही हैं। ऐसी सुंदरियां पंजीयक तोमर से लेकर आठों बैठे उपपंजीयकों तक को अपनी मुस्कानों और आकर्षक अंग-प्रत्यंगों के प्रदर्शन कर अपने खेल कर गुजरती हैं। बाद में आई.सी.आई., एचडीएफसी, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया व अन्य अनेकों बैंको और उनकी शाखाओ उनकी गृह ऋण वित्त कंपनियों, सहकारी संस्थाओं से ऋण दिलवाने के कार्यों में संलग्न हैं। इन सुंदरियों के यौवन का रसपान कर ये शूकरों की फौज आंख मींचकर सारे फर्जी कामों को भी अंजाम देने में लगी है। फर्जी रजिस्ट्रियों, फर्जी सर्च रिपोर्ट्स, फर्जी मूल्यांकनों के सहारे भी ऋण खातों, गिरवी रखने, मुख्त्यार नामे के आधार पर भी करोड़ों के पंजीयन शुल्क की चोट शासन को दी जाने का खेलभी बरसों से यहां अंजाम दिया जा रहा है, परन्तु जिला उप पंजीयकों से लेकर जिला पंजीयकों, मुद्रांक महानिरीक्षक, प्रधान सचिव और मुख्य सचिव और मंत्रियों तक इस खेल में सभी शामिल हैं। इसलिए कोई भी भ्रष्ट धूर्त कुछ भी कहने को या इस लूट खसोट पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं अगले अंकों में पढ़िये श्रीवास्तव भदौरिया के फर्ज पंजीयनों और अय्याशी के कारनामे.....

म. प्र. लो.नि. कार्य.यं. बंसल के कारनामे

इंदौर के लोक निर्माण विभाग में विद्युतकीय और रखरखाव कार्यपालन अभियंता वैसे तो हरामखोर करोड़पति बाप की औलाद बताता है, परन्तु यह धूर्त बंसल कैसे लाखो के घोटाले हर महीने कर रहा है इसकी छोटी सी बानगी-

1. हर महीने क्रास बिलिंग इंदौर उज्जैन की यहां की वहां और वहां की यहां करवा कर औसतन रु. 5000 के 30 से 50 बिल हर माह बिना निविदा बुलाए बिना सामान खरीदे ही ठेकेदारों से सीधे फर्जी बिल लेकर भुगतान कर पैसा डकार लिया जाता है। पिछले दो वर्षों में लगभग रु. 1 करोड़ से ज्यादा का इस प्रकार घोटाला बंसल द्वारा किया गया।
2. बंसल के कार्यालय के अंतर्गत इंदौर के सभी बड़े शासकीय विभागों जिसमें जिला व केन्द्रीय जेल, एम.वाय. चिकित्सा महाविद्यालय, जिलाधीश, आयुक्त, मोती बंगला रेसीडेंसी जैसे विशाल भवनों के विद्युत और यांत्रिकीय आदि की जिम्मेदारी है। इस हरामखोर के अंतर्गत सभी भवनों के लिए विद्युत पर पिछले तीन वर्षों में किए गए व्ययों उससे खरीदी गई सामग्री का स्कंध की जांच की जानी चाहिए जहां स्टाक के नाम पर केवल कबाड़खाना भरा हुआ है। एम.वाय. की लिफ्ट भी इसी के अंतर्गत आती है। ये धूर्त उसके रखरखाव का सारा पैसा डकार जाता है। लिफ्ट वहीं की वहीं खराब पड़ी रहती है।
3. इसके अंतर्गत विभाग के सभी वाहनों के रखरखाव की भी जिम्मेदारी है। कई वाहन मिस्त्री के यहां पहुचते न पहुंचते डीजल पेट्रोल के साथ मरम्मत के जाली बिल जरूर स्वीकृत होकर डकार लिए जाते हैं।
4. उज्जैन का लोक निर्माण विभाग और यांत्रकीय अभियंता सोनकर भी इस की इन जालसाजियों में शामिल है। इन दोनों की क्रास बिलिंग की जालसाजियों की जांच की जानी चाहिए।
5. 5 वर्षों के नील ट्रेडर्स भोपाल से बिना टेंडर्स कितने के बिल भुगतान किए।

विस्तृत रिपोर्ट अंगले अंकों में....

भ्रष्ट अय्याश को दिया महिला बाल विकास

भ्रष्ट मोहंती को बनाया महिला बाल विकास सचिव

मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर भी वर्तमान केन्द्रीय मंत्री मानव संसाधन अर्जुनसिंह कांग्रेसी मंत्री हो, परन्तु भूतपूर्व यह मुख्यमंत्री अभी भी पूरी म.प्र. की राजनीति का मुखिया है। उसी के इशारे पर भाजपाई मुख्यमंत्री भ्रष्ट, हरामकोरों की ताजपोशी भ्रष्टाचार से धन कमाने वाले विभागों में कर रहे हैं। इस भाजपाई मुख्यमंत्री की क्या औकात है जो ये भ्रष्ट शूकरों के झुंड में घुसकर उन्हें खदेड़ेगा। ये तो उल्टे ही ऐसे भ्रष्टों को भ्रष्टाचार और अय्याशी के लिए उस विभाग के सर्वेसर्वा बनाकर ताजपोशी कर रहा है, ताकि खुद भी कुछ धन कमा सके।

भोपाल। दिल्ली से लौटते ही बाबूलाल गौर ने यहां भ्रष्ट अय्याश दिग्गी दानव और अर्जुनसिंह के चेले मोहंती को महिला बाल विकास का ही आयुक्त और सचिव बना दिया, ताकि उसमें चल रही सैंकड़ों योजनाओं में प्राप्त होने वाला केन्द्रीय राज्य का, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त धन को डकार सके और उसके हिस्से की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के लिए की जा सके।

मोहंती न केवल भ्रष्ट, लुटेरा, शूकर अय्याश भी है उसमें कार्यरत महिलाकर्मी, महिला कार्यकर्ता जो शासकीय व पूरे प्रदेश में फैले अशासकीय संगठनों महिला बालवाडियों में कार्यरत हैं धन की स्वीकृति आदि के लिए इसके सामने प्रस्तुत होगी ही, ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके, जो इस अय्याश की अंकशायिनी बनेगी। उसको ही सारी शासकीय सुविधाएं मिलेंगी जो इसके सामने नहीं लेटेगी उसे अनेकों ढंगों से प्रताड़ित किया जाएगा और विवश किया जाएगा, ताकि या तो वो स्वयं इसके आगोश में चली जाए या इसके अन्य महिलाओं की व्यवस्था करे। यह सब करने के बाद ही उसको धन मिलेगा, जिसमें से शेर का हिस्सा ये भ्रष्ट शूकर शू-शू करते डकार लेगा। इस भ्रष्ट ने पूर्व में म.प्र. औद्योगिक केन्द्रीय विकास निगम में खाद्य विभाग में इंदौर का जिलाधीश रहते हुए व अन्य सभी पदों पर रहकर अरबों रुपये के घोटाले किए हैं।

दिग्गी दानव के पांच पांडवों में एक भ्रष्ट पांडव यह भी था। इसके बाद भी भाजपाई मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने इसे महिला बाल विकास ही सौंप दिया जबकि भाजपा ने बड़े-बड़े दावे किए थे। भ्रष्टाचार को खत्म करने के, परन्तु ये हरामखोर तो स्वयं चाहे वो उमा भारती ही पाखंडी संन्यासिन हो या बुलडोजर मंत्री सबके सब उस महाभ्रष्ट भूतपूर्व मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह की कठपुतली बन ही नाच रहे हैं। सब जाकर दंडवत करते हैं उसे दिल्ली में। जैसा वो कहता या निर्देशित करता है। उसके संगीत की धुन पर ही ये ताल मिलाते हैं। अर्थात इनके अपने वादों की कोई कीमत नहीं फिर चुनावी वादा तो चुनाव खत्म होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। यदि सत्ताधारी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो ये सत्ता में बैठे क्यों हैं? मात्र लूटने के लिए तो उन्हें भी भ्रष्ट अय्याश और लुटेरे ही चाहिए जो स्वयं कमाएं कैसे भी, चाहे नाड़े खुलवाकर या नाड़े खोलकर इन्हें तो कमाई से मतलब है। आखिर अनुभवी भ्रष्ट शातिर ही तो चाहिए। सत्ताधारियों को जो बिना किसी लाग-लपेटे के कमाई का हिस्सा मुखिया को सौंप दे।

B.H.M.S.सत्र 2004-2005 में प्रवेश

बैचलर ऑफ हौम्योपैती मेडिसीन एंड सर्जरी

5 1/2 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (एक वर्षीय इंटर्नशिप सहित)

मान्यता-देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं सेन्ट्रल कौंसिल ऑफ होम्योपैथिक, नई दिल्ली

पात्रता-12th (फिजिक्स, केमेस्ट्री एवं बायोलाजी विषय के साथ 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण) या पी.एच.यू.टी. उत्तीर्ण छात्र

परामर्श एवं तत्काल प्रवेश प्रक्रिया

नोट- प्रवेश म.प्र. शासन के निर्देशानुसार
प्रवेश हेतु अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ महाविद्यालय में निम्न पते पर स्वयं संपर्क करें।
प्रवेश हेतु अंतिम तिथि

इंदिरा गांधी मेमोरियल
होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय
131, प्रकाश नगर धार (म.प्र.)
दूरभाष 07292-234488, 506150
मो. 8272-10150, फैक्स 506150

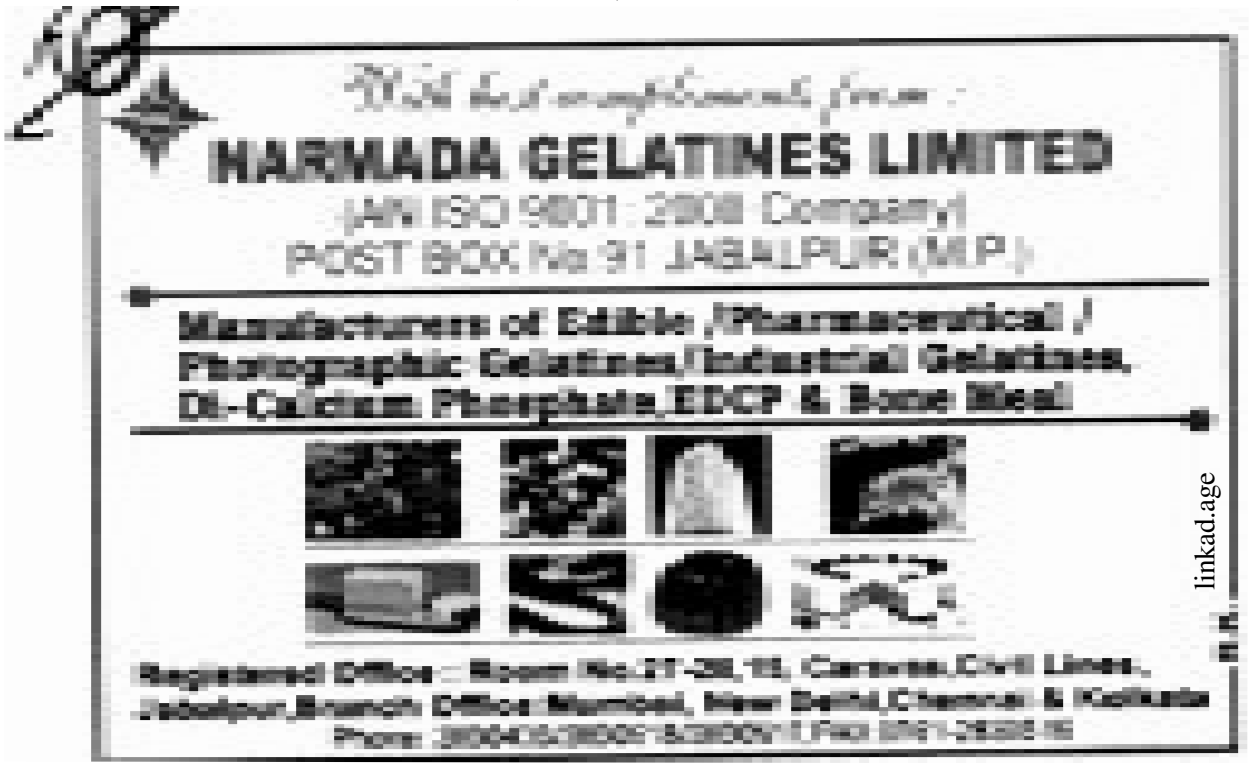

आरक्षित वर्ग को नौकरी दो और जेल जाओ

वोटों की राजनीति, नियोक्ता को कटोरा थामने के लिए मजबूर कर देगी

भ्रष्ट मनमोहन सिंग ने कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते ही वोट कबाड़ने और भ्रष्टाचार से धन कमाने के लिए अर्जुनिये पैंतरे चलने शुरू कर दिए हैं। आरक्षित वर्ग के ईमानदार मेहनतकश लोगों की आरक्षण कर निजी क्षेत्रों में ज्यादा तरीके से जिंदगियां बर्बाद करेंगे, क्योंकि इस तथ्य को जबरर्दस्ती थोपने पर स्वाभाविक है कोई भी नियोक्ता उद्योगपति इस वर्ग के भ्रष्ट, हरामखोर, कामचोरी की नेतागिरी की प्रकृति वाले को अपने यहां काम पर नहीं रखेंगे जो मेहनतकश और ईमानदारों के साथ घात होगा। क्योंकि ऐसे आरक्षित वर्ग के मेहनती और ईमानदारों को आरक्षण के चक्कर में उलझ कर फैक्ट्रियों, उद्योगों में अगर कामचोरों, नेतागिरी करने वालों को शासकीय नियमों और दवाब में नौकरी दी जाएगी तो स्वाभाविक है उद्योगपतियों, फैक्ट्री मालिकों को अंत में हानि होगी और ताले डालकर कटोरा थामना पड़ेगा।

भ्रष्ट, मक्कार, लुटेरे, हरामखोर कांग्रेसियों ने देश की हालत अपने स्वार्थों और सत्ता पर कुंडली मारकर बैठे सत्ता के दुरुपयोग के लिए क्या कर दी, यह न केवल देशवासियों बस दुनिया को भी मालूम है। वोटों की राजनीति के चक्कर में ये किस हद तक गिर जाएंगे। इसकी सच्चाई जनसंख्या के तुलनात्मक सांख्यिकीय स्पष्ट करती है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आक्षण देकर उनके धन को न केवल सत्ताधीश वरन उच्चाधिकारी भी जीमते रहे हैं.

इस बात को केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण मंत्री कांतिलाल भूरिया ने भी अपने इंदौर प्रवास के दौरान समय माया को दिए गए साक्षात्कार में भी स्वीकार किया कि शासन से मिलने वाला धन नीचे तक पहुंतचे-पहुंचते जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सरपंच मिलकर डकार जाते हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण के मु-े पर जो ईमानदार मेहनतकश आरक्षित वर्ग के लोग हैं वे बहुतायत से निजी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यदि शासकीय आरक्षण सौंपा गया तो स्वाभविक रूप से स्थिति बिगड़ेगी और फिर अभी जो जातिवादी वैमस्यता निजी क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ती और उभरी है। वह जातिवादी वैमस्यता निजी क्षेत्र में बढ़ेगी और उसका असर भी दिखेगा।

यदि केन्द्र सरकार आरक्षित वर्ग को निजी क्षेत्र में जातिवादी तरीके से फैलेगी तो निजी उद्यमियों के अनुसार क्या शासन उनको अतिरिक्त सुविधों देने के लिए क्या सीधे अनुदान देगी, विक्रय कर, आय कर व अन्य करों में छूट देगी। यह सब तो सरकार कंगलेपन और भूखे भेड़ियों की फौज के कारण नहीं दे सकेगी। उल्टे ही उनको कागजी खानापूर्ति और नियम कानूनों के चक्कर में उलझा कर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के युग में आर्थिक बोझ बढ़ाने में व उद्योगों को बंद करवाने की भूमिका अवश्य निभाएगी।

वोटों की गंदी राजनीति के चलते मनमोहन की चुनावों में आरक्षित सीट खींचने की ये मोहनी निजी क्षेत्र में लागू करने पर निजी क्षेत्र तो विपरीत दिशा में जाएगा ही साथ ही निजी क्षेत्र से शासन को होने वाली करों की आय पर भी विपरीत असर पड़ेगा।

आरक्षित वर्ग को यदि निजी क्षेत्र के उद्यमियों ने आरक्षित वर्ग के आधार पर नौकरी दी तो स्वाभाविक है कि वो अधिकतम धन को दोहन करने के साथ ही काम भी न्यूनतम या बिल्कुल नहीं करेंगे और यदि कार्यवाही की गई तो उल्टा ही वो पुलिस कार्यवाहियों की धमकी देकर उद्यमियों पर दबाव बनाने की राजनीति अपनाएंगे जो उद्यमियों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ना होगी, जिसका स्वाभाविक असर व्यवसाय पर पड़ेगा। जो हानि की स्थिति उत्पन्न करेगा। जो भारी घातक होगा। शायद जो अभी शासकीय कार्यालयों में चल रहा है। जहां पर चपरासी भी आई.ए.एस. तक धमका देता है। काम नहीं करता वो अलग। यदि काम करता है और भ्रष्टाचार करता है जिसकी प्रताड़ना भी उस अधिकारी को झेलनी होती है। इसलिए आरक्षित वर्ग में नियुक्त कर्मचारी से अधिकारी तक शासकीय विभागों में बिरले ही होंगे, जो वास्तविकता में वेतन के बदले कर्त्तव्य परायणता दिखाते हो, खुलकर भ्रष्टाचार करना या फिर काम न करना यदि कोई अधिकारी उनसे काम के लिए कहे तो प्रताड़ना का आरोप लगाना जैसे उनकी दिनचर्या ही बन गई है। इस संदर्भ में मान दाहिमा और पुत्र ललित दाहिमा के कर्मकांड देखे व सुने होंगे, जिन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले किए, यदि निजी क्षेत्र में भी इसी आधार पर नौकरी देकर उद्यमियों को यही सब झेलना है। तो ऐसी व्यावसायिकता से उपजी परेशानियों से बेहतर उद्योग ही न लगाएं जाएं, ताकि कानूनी झंझटों से बचा जा सके।

क्या हरामखोर मनमोहन और निकम्मा पूरा केन्द्रीय मंत्रिमंडल अपने वोटों की खातिर पूरे देश को बर्बाद करेगा।

आखिर क्यों म.ब्रा. स. बैंक का लाइसेंस निरस्त

''सहकारिता के कर्णधार मिल करें सदस्यों का बंटाढार'' महाराष्ट्र ब्राह्मण कर सहकारी बैंक मर्या. में अध्यक्ष पद पर वर्षों से कुंडली मारे बैठे अजगरों ने जनता के पैसों से पूर्ति नामक बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स अपने रिश्तेदारों के नाम से खोलकर अधिकांश पैसा वहां लगा दिया, फिर रिश्तेदारों को अध्यक्ष और संचालक मंडल ने जनता की जमाओं से जो ऋण दिए उसको भी संचालक मंडल के सदस्यों के रिश्तेदारों में बांटा तो गया पर वसूली किस बात की। आपलाज मानुष आहे, ऋणा ची जेवन झाली, ने झोपण आली, जमाकर्ता भटकेगा तो भटकने जो ज्यादा था तभी तो जमा किया। जब ''समय माया'' ने मीडिया वर्ल्ड कन्युनिकेशन के नाम से न केवल पत्र बैंक अध्यक्ष वरन सहकारिता के संयुक्त संचालक सन 2000 से जितने भी रहे सबको दिए पर न उन्होंने जवाब दिये न शूकरों की फौज संयुक्त संचालक व उसके विभाग कर्मियों ने क्योंकि इन्हें तो सहकारिता के कर्णधार ही अपने कुकर्मों की गंदगी परोस कर ही पालते हैं। तो फिर ये कैसे किसी कर्णधार पर कार्यवाही करेंगे।

99% सहकारी संस्थों फिर चाहे वह बैंकिंग, साख, गृह निर्माण, विपणन, कृषि वन उपज से लेकर सभी सहकारी संस्थाओं के कर्णधार जो बड़े दादा, गुंडे, पहलवन, कांग्रेसी नेता, विभागीय नेता, माफिया सरगना ही होते हैं। सबका एक ही ब्रह्म वाक्य होता है ''सहकार सदस्यों की पूंजी का लाभ के नाम पर करो बंटाढार।'' अधिकांश अध्यक्ष, सचिव, संचालक आखिर कौन

(शेष पेज 6 पर)

महाभ्रष्ट उपायुक्त, संपत्ति प्रबंधक अभियंता द्वारा

म.प्र. गृह मंडल में हो रहे करोड़ों की जालसाजी बिना गृह नि. मंडल को धन दिए हो गई सैंकड़ों रजिस्ट्रियां

इंदौर म.प्र. गृह निर्माण मंडल के उपायुक्त कार्यालय में कदम-कदम पर जमीन की खरीदी से लेकर विकास आवंटन, अनापतत्ति प्रमाण पत्र, पंजीयन, स्थानांतरण किश्तों के भुगतान, पट्टों का किराया, शासकीय और मंडलों के गृह निर्माण, कार्यालय कारावास आदि में भी उपायुक्त से लेकर संपत्ति प्रबंधकों, अभियंताओं से लेकर बाबुओं तक कदम-कदम पर कैसी लूटमार करने के लिए जालसाजियों का भ्रष्ट हरामखोरों द्वारा अंबार लगा दिया गया है। एक ताजा उदाहरण गृह निर्माण के आदेश क्र. 1350 सं./अ./102 इंदौर दिनांक 13-2-2002 को आवंटित श्री मांगीलाल सोनी को आवंटित प्लाट रु. 2,16,475/- पत्र की प्राप्ति से 30 दिन के अंदर जमा कराने थे जो आज तक जमा नहीं हुए। इसके विपरीत प्लाट आवंटित होकर संयुक्त नाम में परिवर्तित हो गया और 20-2-2003 को पत्र क्र. 376/सं.अ. 99/20/2/2003 को अनापत्ति दिया जाकर 27-10-2004 को इस विक्रय नामा भी लिखा जा चुका है, जिसका क्र. 29475/104 है। जबकि उसी उपरोक्त आदेश में शर्त क्र. 2 के अनुसार प्लाट 3 वर्ष तक अहस्तांतरणीय हैं। ऐसे संपत्ति प्रबंधक पर लगभग 50 प्रकरण हैं, जिसमें गुप्ता और यादव ने प्लाट बाले-बाले बेचकर लगभग रु. 1 करोड़ से ज्यादा की जालसाजी की है। ऐसे ही सुखलिया की बगीचे की जमीन जो लगभग 1 एकड़ से ज्यादा थी यादव और गुप्ता ने मिलकर भू-माफियाओं को बेच दी। जिसके नक्शे की छायालिपि यहां है। जबकि उपायुक्त यादव को गुप्ता की ऐसी जालसाजियों के लिए एफ.आई.आर. आईपीसी धारा 420 के अंतर्गत लिखवा कर तुरंत जेल भिजवाना चाहिए था, परन्तु यादव स्वयं ऐसी सैंकड़ों जालसाजियों में स्वयं हिस्सेदार है तो वह धूर्त हरामखोर क्या एफआईआर लिखवाएगा।

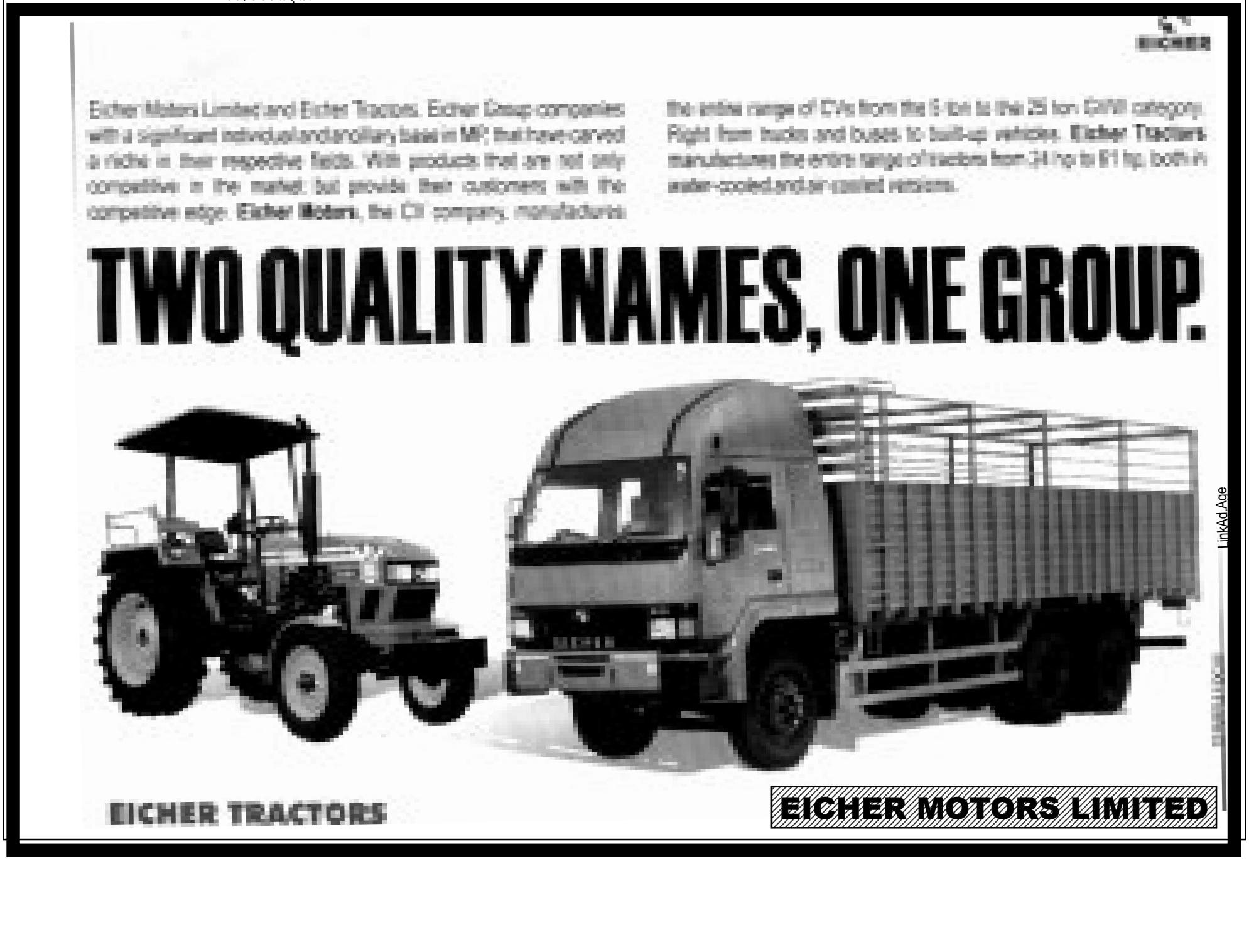

भ्रष्ट विभागों में अचानक छापे क्यों नहीं पड़ते?

कार्यालय का समय समाप्तिके बाद कर्मचारियों की तलाशी ली जानी चाहिए

हर वर्ष 25 प्रतिशत को नौकरी से हटाओ, बेरोजगारों को नौकरियों दें

मुंह चलाने वाले मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जनता, कैमरे और प्रेस के सामने तो बड़ी-बड़ी भाषणबाजियां भ्रष्टाचार के विरुद्ध करते हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि वो भी सारे शूकरों की फौज हैं तो उसी भ्रष्टाचार का हिस्सा यदि वो चाहें तो शासकीय भ्रष्टाचार को तीन दिन में खत्म हो सकता है। जितने भी भ्रष्ट विभाग हैं जैसे परिवहन, न्यायालय, पंजीयन, विक्रय कर, आयकर, नगर निगम, शिक्षा, जिलाधीश कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र व अन्य वे सभी जहां जनता से कार्यालयों में वसूलियां होती हैं वहां पर कर्मचारियों के घुसने पर तलाशी ली जाए और बाहर निकलने पर अपने आप वसूले गएधन के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने पर निलंबन और 15 दिन में नौकरी से छुट्टी। इस प्रकार आई.ए.एस. से लेकर चपरासियों तक को 10 से 25 प्रतिशत हटाओ। नए रोजगारों को नौकरियां दो। पेंशन भी बचेगी। नए आनी वाली पीढ़ी को रोजगार के साथ नई कार्यशील पीढ़ी की नई आधुनिक कम्प्यूटर शिक्षा प्रणाली का देश में सदुपयोग हो सकेगा।

भाजपा ने राज्य में और कांग्रेस ने केन्द्र सरकार में सत्ता संभालने पर जनता से वादा किया था कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे, पर सच्चाई इसके विपरीत भाजपा राज्यों में और कांग्रेस व उसका संयुक्त, प्रगतिशील गठबंधन दिनों दिन भ्रष्टाचार में अपनी प्रगति के रिकार्ड बनाने में लगे हैं।

यदि शासन चाहे केन्द्र का हो या राज्यों का कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार से न केवल मुक्त हो सकता है लाखों कर्मचारियों को रंगे हाथों भ्रष्टाचार में पकड़कर नौकरी से बाहर कर लाखों लोगों को रोजगार भी दे सकता है। इससे एक तो केन्द्र व राज्य शासन में बुढ़ा चुकी फौज का भी सफाया होगा वरन् नई युवा पीढ़ी की शिक्षा और आधुनिक तकनीकी काम बिना किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण के राष्ट्र और विश्व की जनता को लाभ मिल सकता है। इससे न केवल कार्यों में गुणवत्ता आएगी, बल्कि राष्ट्र की छवि सुधरेगी। शासन के सिर से पेंशन बोझ घटेगा। विश्व के प्रतियोगी बाजार में उसकी साख बढ़ेग। विदेशी निवेश व आधुनिक तकनीकी का राष्ट्र को लाभ मिल सकेगा।

इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकारों को कुछ खास नहीं करना पड़ेगा। बस घुसने से पहले उनकी जेबों में और साथ में चल रहे सामान अर्थात या ब्रीफकेस में क्या है। कार्यालय की समाप्ति पर घर जाते समय क्या है का अंतर और कार्यालयों में लगे कैमरों की रिकार्डिंग से भ्रष्टाचार की पुष्टि होते ही स्थल पर ही निलंबन और 15 दिन में तीन माह के वेतन के साथ हमेशा के लिए छुट्टी की व्यवस्था कर हर वर्ष 10 से 25 प्रतिशत कर्मचारियों, जिसमें महाभ्रष्ट शूकरों की फौज आईएएस से लेकर चपरासियों तक सब के स्थल पर निलंबन और 15 दिन में नौकरी से हटाने की पक्की व्यवस्था हो तो भ्रष्टाचार सप्ताह से 15 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, परन्तु इसके लिए ठोस इच्छा शक्ति चाहिए।

ऐसे भ्रष्ट विभागों में केन्द्रीय आयकर, डाक तार, रेलवे, केन्द्रीय, कस्टम एंड एक्साइज, केन्द्रीय लोक निर्माण, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सर्तकता आयोग से लेकर राज्यों में पंचायत के सचिवालय से चलकर राज्य शासन के सचिवालयों में बैठे भ्रष्ट आईएएस, परिवहन, वाणिज्य कर, पुलिस, नगर निगमों, आवासीय मंडल, शिक्षा सभी नगर प्राधिकरणों, कोषालयों, खाद्य, तहसीलों कार्यालय, आबकारी, जिलाधीश कार्यालय, आदिवासी जनजाति कल्याण, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत मंडलों, पंजीयन कार्यालय, कृषि विभाग आदि वे सभी विभाग जहां कार्यालय की मेजों पर पैसे गिने जाते हैं। इस प्रकार से कर्मचारियों को रंगे हाथों भ्रष्टाचार के धन के साथ और कार्यालयों में लगे कैमरों की रिकार्डिंग से पुष्टि कर निपटाया जा सकता है। जहां पैसों का लेन-देन बाहर ही हो सकता है। जैसे पुलिस, लोक निर्माण, मिलिट्री जिसमें जल, थल और नभ सेनाएं, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य, नगर व ग्राम निवेश, जिलाधीश, संपत्ति की खरीद बिक्री का पंजीयन जिसमें उपपंजीयक, पंजीयक मोहर्रिर बाहर क्रेता-विक्रता से मकानो, फैक्ट्रियों और अन्य स्थापनाओं के बदले जिसमें दुकानों, गोडाउनों, सिंचित कृषि भूमि के स्थानों पर प्लाटों, असिंचित भूमि या खराब भूमि के रूप में पंजीयन करवा के बाहर ही लेन-देन कर लेते हैं। अंकेक्षक सहकारी समितियों के महालेखाकार कार्यालय के, बीमा मूल्यांकन कर्त्ता, न्यायाधीश आदि जो बाहर लेन-देन कर लेते हैं। इनकी हर गतिविधियों पर फोनों, मोबाइलों को टेप करके इनकी व इनके परिवार की खरीद बिक्री और बैंक खातों पर सतत नजर रखकर भी भ्रष्टाचार के धन के साथ पकड़ा जा सकता है। बशर्ते उच्च भ्रष्ट अधिकारियों की आत्मीय इच्छा होना चाहिए कि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवर सके, पर इनके सबके लिए जरूरी है कि भ्रष्टाचार का अंत केवल शासकीय विभागों से ही नहीं वरन शिक्षा की दुकानों से भी भ्रष्टाचार को खत्म किया जाना चाहिए, ताकि वो ईमानदारी और कड़ी मेहनत के प्रति

(शेष पेज 6 पर)

निकम्मा भ्रष्ट वीसएनएल अब लुटेरा झुठेला भी हो गया

भारत संचार निगम लि. के लाइनमेन से महाप्रबंधक तक भ्रष्ट तो थे ही। अब जनता से अनाप-शनाप बिलिंग करना और व्यर्थ की झूठी घोषणाएं करने वाला हो गया है।

नए कनेक्शनों में फिटिंग की जगह सीधा तार लटका कर कनेक्शन की डिब्बी यहां वहीं दीवार या किसी भी सहारे पर बांध कर पूरे कनेक्शन शुल्क उपभोक्ता से वसूल कर लिया जाता है। जिसका पूरा पैसा संबंधित लाइनमेन, सुपरवाइजर, सहा. अभियंता, अभियंता से लेकर महाप्रबंधक निगम तक बंट जाता है। हरामखोरी यहां से बढ़कर तरंग और मोबाइल फोनों में भी चलती है। निजी कंपनियों से करोड़ों डकार कर ये शूकरों की फौज जानबूझकर अपनी सेवाएं बिगाड़ कर न केवल उपभोक्ताओं वरन पूरे निगम को बदनाम कर रही है। उसकी सिम आते ही अग्रिम भुगतान की काउंटर पर दो घंटे बाद समाप्ति की घोषणा कर दी जाए पर कश्मीर से कन्या कुमारी तक बंबई से आसाम-नागालैंड तक दलालों के माध्यम से 200/- की 10,000 तक ब्लैक में आज भी उपलब्ध है।

सियासतदार तो विक्रेता हुए हैं। कोई दाम तो लगाए। ये सियासत के हरामखोर झोले खोले हुए हैं। यह शासकीय दूर संचार निगम जो अब भारत संचार निगम बन गया है कि कहानी भी अब पूर्णत: इसी तर्ज पर चल रही है। 50 वर्षों तक कश्मीर से कन्या कुमारी और बंबई से कोहिमा, इंफाल तक भी इसका साम्राज्य है। इसके सियासतदार या अधिकारी हर कदम पर न केवल बिकने को तैयार खड़े रहते हैं वरन अब ये शूकरों की फौज दूसरी फोन और मोबाइल कंपनियों की तरह बिलिंग में भारी घोटाले करके अवैध रूप से अपने खर्चों, वेतन और भ्रष्टाचार के घाटों की आपूर्ति अपने ग्राहकों से कर रही है।

ये हरामखोर बंदरबांट में डकार रहे हैं। इन्हें मतलब नहीं कि भारत संचार निगम कल का डूबता आज डूबे। छंटनी की तलवार में कहीं ये उड़ाए गए तो इसलिए आज ही डकार लो फिर चाहे निजी क्षेत्र की कंपनियां पैसा खिला कर यदि कनेक्शन काटने केलिए भी कहें तो वह भी करो, क्योंकि अब तीन-तीन कंपनियों के फोन भी उपलब्ध हैं। ये उन हरामखोरों के इशारे पर नाचने लगे हैं। जानबूझ निगम के मोबाइलों की तरंग दैर्ध्य घटा देते हैं। ताकि नेट वर्क बिगड़े और निगम के चलित दूरभाषों की तरफ न लपकें, जिससे निजी कंपनियों की ग्राहक संख्या न घटे। वर्तमान हालात ये हैं कि अगर 5 लाख चलित दूरभाषों की अग्रिम भुगतान बाजार में डाल दी जाए तो म.प्र. और छत्तीसगढ़ में रिलायंस, आइडिया और एयरटेल जैसे लुटेरे गिद्धों को चलित जी.एस.एम.के. पूरे म.प्र. और छत्तीसगढ़ के कार्यालयों में ताले डालने पड़ेंगे। इसलिए निजी चलित भाषों की कंपनियां इनके बड़े-बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को खुल कर पैसा बांटती है तो ये जानबूझकर तरंग दैर्ध्य में उच्चाबचन निर्मित कर संचार प्रणाली को बाधित कर देते हैं। इससे इन हरामखोर अधिकारियों और कर्मचारियों को भले ही तात्कालिक कोई दोष नजर नहीं आए पर दीर्घ गामी परिणाम छोटे कर्मचारियों को ही भुगतने पड़ेंगे। फिर इनके कुकर्मों से 150 वर्षों का इतिहास की छवि और विश्वास भी बिगाड़ रहे हैं। बाजार में विश्वास और ईमानदारी सदा ही अनमोल और सर्वोपरि रही है।

देश में महाभ्रष्ट गिद्धों की कांग्रेस सरकार के आते ही इतने भी बिलिंग में घोषणाओं के विपरीत ग्राहकों को भ्रम में डालकर कि इंटरनेट पर रात में 10 बजे से सुबह आठ बजे तक और रविवार व राष्ट्रीय अवकाश के दिन 24 घंटों में 10 मिनिट की एक कॉल होगी। कहकर जब ग्राहकों ने इंटरनेट चलाया तो उसकी बिलिंग भी मोबाइल की एक मिनिट की तरह ही कर डाली, जिससे जहां एक कॉल जो 10 मिनिट का होना था वह 1- मिनिट का भुगतान रु. 12.60 किया गया और एक घंटे का इंटरनेट रु. 72, साथ रु. 4.20 का शुल्क 6% की दर से 2% शिक्षा उपकर आदि मिलाकर रु. एक घंटे लगभग 60 रु. हो गया। अधिकांश जिन कनेक्शनों पर इंटरनेट था उनकी बिलिंग एकदम डेढ़ गुनी हो गई।

घोटालों की ये कहानी ग्राहकों की जेब पर पड़ी। राजस्व बढ़कर इन हरामखोरों का समायोजन हो गया। इनके भ्रष्टाचार में फिर नए कनेक्शनों में जहां फिटिंग होनी थी लाइनमेन ने डिब्बी यहां वहां तार से कील से खूंटी से बांधकर लटका दी रु. 275 कनेक्शन चार्ज ग्राहक से वसूला गया। उसका पैसा लाइन मेन, सुपर वाइजर से लेकर ठेकेदार और महाप्रबंधक तक की जेब में चला गया। लाइन बिछाने से लेकर आप्ररेशन एंड मेंटीनेंस में लगने वाली मरम्मत सुधार

(शेष पेज 6 पर)

इंदौर प्रेस क्लब बताए कि.....

✦कि क्या तुम्हारे क्लब में पूरे इंदौर के साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्रों के मालिक या प्रतिनिधि ही सदस्य हैं या अन्य अनेकों उनके रिश्तेदार जिनका प्रेस से कोई संबंध नहीं, भी सदस्य हैं।

✦जब इदौर प्रेस क्लब नाम है तो साप्ताहिक समाचार पत्रों को सदस्यता क्यों नहीं?

✦जब प्रेस क्लब नाम है तो ओटीजी जो दृश्य माध्यम से संबंधित है उसे क्लब में सदस्यता और प्रश्न पूछने का अधिकार क्यों?

✦केन्द्र के भूतल परिवहन मंत्री के कहने पर समय माया के श्री अजमेरा ने यदि उनका साक्षात्कार लिया तो सतीश जोशी ने उनका अपमान क्यों किया? उन्हें प्रश्न पूछने से क्यों रोका?

✦म.प्र. कैमरा क्लब के नाम पर कितना पैसा उगाया गया। लाखों में उगाही गई रकम जो इंदौर वासियों से वसूली गई थी क्या फैशन शो की मॉडल वैश्याओं को बुलाने के लिए थी। फैशन शो करवा कर जनता को क्या संदेश दिया कि प्रेसकर्मी भी रंगरेलियों के शौकीन ज्यादा हैं।जनता के भले के लिए कलम चलाने के कम।

✦जो लाखों रुपए का चंदा बड़े-बड़े माफियाओं, नकली दवाइयों, नकली घी, नकली सामान, आयकर, वाणिज्य कर चोरों, नगर निगम, पुलिस प्रशासन, सटोरियों, जुआरियों, होटलों में वैश्याओं के अड्डे चलाने वालों से आता है। क्या चंदा पदाधिकारियों नहीं डकार लिया जाता। यही कारण है 70% ऐसी खबरें राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आ जाती हैं, परन्तु इंदौर प्रेस क्लब ऐसे भ्रष्टों और निकृष्टों को कभी जनता के सामने नहीं लाता।

✦प्रेस मीडिया जनता की भलाई में क्या कर पा रहा है। जब अवैध कालोनियां कटती हैं, जुए-सट्टे और वेश्याओं के अड्डों से, जिलाधीश कार्यालय लें, नगर निगम, पुलिस थानों से, आबकारी, महिला एवं बालक विकास, माध्यमिक शिक्षा मंडल, बड़े-बड़े जालसाज स्कूल, कालेजों, नकली आभूषण बनाने वालों, नकली दवाइयां, मिलावटी खाद्य सामग्री, नकली मिलावटी पेट्रोल, जालसाजी पूर्ण अचल संपत्तियों की खरीद, बिक्री, भू-माफियाओं, नेताओं, गुंडों, अपराधियों के तांडव, नकली व मिलावटी पान मसालों, गुटकों, शराब के अड्डों पर, 250 नर्सिंग होम्स 200 ज्यादा पैथोलेब्स, नपुंसकता दूर करने वालों, बच्चे पैदा करने के नाम पर लूटने वाले महिला-पुरुष चिकित्सकों, ब्यूटी पार्लर और हेल्थ सेंटर के नाम पर चलने वाले महिला पुरुष वैश्याओं के अड्डों से देशी घी के नाम पर सुअर की चर्बी, पामोलीन बेचने वालों से, मसालों के नाम पर मिलावट करने वालों से, 20 से ज्यादा 700 सरपंचों से खरीदने वाले शासन के गेंहू से आटा, मैदा, सूजी बनाने वालों से, केवल वसूली कर रहे हैं। या सीधे विज्ञापन छापकर जहां जनता के साथ खुले में जालसाजी और धोखाधड़ी होती है। इनको सच्चाई उजागर करने और जनता को बचाने की अपेक्षा केवल वसूली कर सब कुछ जानने के बाद भी क्यों चुप रहता है, क्योंकि उनके विज्ञापनों से करोड़ों की कमाई होती है।

✦कैलाश विजयवर्गीय मंत्री म.प्र. शासन ने खुले में कहा पत्रकार जूठन चाटने वले श्वानों की फौज है। परन्तु सतीश जोशी उसका प्रतिरोध तक नहीं कर पाए, क्योंकि ये उसके अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक है सबसे ज्यादा जूठन ये ही चाट रहे हैं।

✦साप्ताहिक समाचार पत्रों की 90% कटिंग काट कर चिपकाने वालों केवल वसूली करके और जूठन चाट कर अपने आपको महान समझने वालों इंदौर प्रेस क्लब चालू करने वाले साप्ताहिक वाले ही थे। जिस पर तुमने कब्जा जमाया। अब तुम उन्हीं को आंख दिखा रहे हो।

(शेष पेज 6 पर)

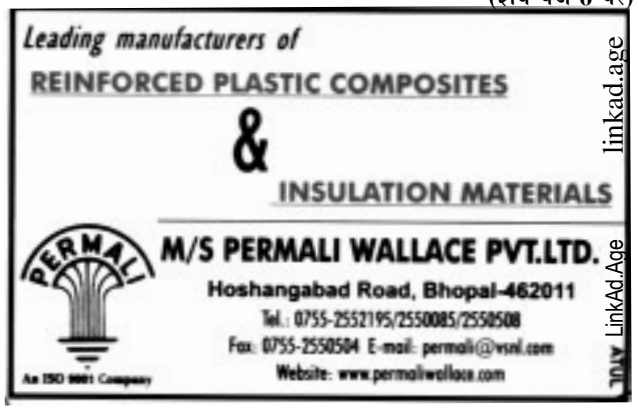

(पेज 8 का शेष) भ्रष्ट सेवक नहीं.....

ै यदि जिंदगी प्राप्त करने की अपेक्षा नर्सिंग होम्स डेथ होम्स बन जाएंगे तो स्वाभाविक है Vऐसे डेथ होम्स के मालिकों को दूसरों को मौत देने वाले की यात्रा का अंत मजबूरन करना पड़ेगा।

सेवा कर जूते खा का नारा लगाने वाले इन गिद्धों की फौज से पूछो कि सेवा के नाम पर तुम बदतमीजों सचमुच आत्मीय रूप से क्या कर रहे हो। केवल नोच, खसोंट, वसूली, जिंदगी के नाम पर क्या दे रहे केवल मौत और मरीजों के परिजनों का आर्थिक शोषण तो फिर त्म अमरफल खाकर तो पृथ्वी पर

अवतरित नहीं हुए। यात्रा का ंअत तो तुम्हारी भी होना ही है तो ठीक है कि तुम न्यायालय से बच सकते हो, नर्सिंग होम एक्ट पर न्यायालय में 10-10 वर्ष तक स्थगन लगाकर मौज कर सकते हो, तलघरों में जहां हवा तक नहीं जाती हो वहां 15 से 50 मरीजों को लेटा कर लाख-लाख रुपए प्रति रात्रि वसूल सकते हो तो तुम्हारे डेथ होम्स के लिए जनता तुम्हारे अन्यायों का अंत कर न्याय क्यों नहीं कर सकती। डॉ. विनोद भंडारी से पूछो कि कितने सैंकड़ा लाशें निकलती हैं जो हंसते बोलते आए थे चिरनिद्रा में निकले। उसके परिजन रोते-बिलखते लेकर निकले वह भी तब जब लाखों के बिल वसूल चुके थे।

जिस पुलिस पर दुनिया आरोप लगाती है वो दुर्घटना ग्रस्त को लेकर पहुंचे चंदा कर इलाज करवाने खून दिया पर ये गिद्ध नहीं पसीजे तो मात्र धन की कमी के कारण। तो ये कैसी सेवा है। हरामखोरं फिर जनता अभी तो मात्र तोड़-फोड़ ही कर रही है। संभल जाओ वर्ना ये डेथ होम्स श्मशाम घाट बनने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। तुम्हारी नौटंकियों का असर अब जनता पर नहीं होता क्योंकि तुमने आटे में नमक की जगह नमक में आटा मिलाने की नीति अपना ली है। नर्सिंग होम्स को नर्सिंग होम्स ही रहने दो डेथ होम्स तुमने बना दिए हैं जनता श्मशान बनाने को उतावली है।

(पेज 8 का शेष)

स्वास्थ्य विभाग में V

ती जो वेश्यों को लायसेंस दिलाने की पक्षधर थीं तो आपके महापौर के रूप में चुने जाने पर कम से कम इंदौरी महिलों को जो बहुविधि, बहु पुरुष आनंद लेकर

जन्हें पुलिस अभी पकड़ते ही वसूली करने के बाद भी बंद कर देती है। हमारी शुभकामनाएं कम से कम आप इस बिना पूंजी, अनादिकाल से चले आ रहे महिलाओं के इस असामाजिक कृत्य को वैधानिक बनाकर नए रोजगार उपलब्ध करवाएंगी। इसमें न पढ़ाई की जरूरत, न पूंजी की, कम से कम महिलाओं की बेरोजगारी घटाने में इस माध्यम से सराहनीय कार्य करेंगी आप।V

(पेज 5 का शेष) निकम्मा भ्रष्ट बीएसएनएल...

जो मशीनों एयर कंडीशनर से लेकर जनरेटर में लगने वाले डीजल में से भी 60% पैसा डकार जाते हैं। न जाने क्यों ये छिछोरी मानसिकता के भ्रष्ट इस अनमोल छवि का नगदीकरण करने की अपेक्षा उसे चंद सिक्कों और बदतमीजियों में जानबूझकर सरे चौराहे नीलाम कर रहे हैं।

नि:संदेह जनता और ग्राहकों के पास विकल्प हैं। इनका देश पर से एकाधिकार समाप्त हो चुका है। इन हरामखोरों की वो औकात बख्त भी नहीं रही। रही सही इज्जत इनकी बदतमीजियों से स्वयं ये बर्बाद कर ही रहे हैं।

कर्मचारियों और कर्मचारी श्रमिक संगठनों को इस निगम की छवि को बरकरार रखने के लिए और अपनी रोजी रोटी को बनाए रखने के लिए ईमानदारी से संघर्ष करना चाहिए अन्यथा सबसे पहले अधिकारियों की बदतमीजियों और भ्रष्टाचार की गाज इन्हीं पर गिरेगी। इसलिए इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अधिकारियों के बारीक से बारीक भ्रष्टाचार से मुक्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा ग्राहक रूपी देवता के रूठने से परेशानी इन्हें ही उठाना होगी।

(पेज 5 का शेष) भ्रष्ट विभागों में अचानक छापे....

विद्यार्थियों को भी सिखा पढ़ा और समझा सकें। इनके सबके विपरीत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब भारत की प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही महा भ्रष्ट, लुटेरे धूर्तों की गंदगी चाटने वाले शूकरों की फौज बैठी हो तो नीचे वाले प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से लेकर बाबू, चपरासी से पूर्ण ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जाए, परन्तु इस प्रथा को उदासीन तो बनाना ही होगा। अन्यथा इसका फायदा उठाने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पूंजीपति देशों का गिरवी हो जाएगा देश।

(पेज 5 का शेष) इंदौर प्रेस क्लब बताए कि.....

✦वर्तमान में प्रेस क्लब में जितने सदस्य हैं उनको सार्वजनिक रूप से दस शहर के जाने-माने बुद्धिजीवियों के दिए विषयों पर 20 मिनिट में 50 लाइन लिखकर दिखाएं, यदि लिखा गया पाठ्य सार्थक हो तो ठीक है अन्यथा सभी ऐसे सदस्यों को बाहर किया जाए केवल भाई-भतीजावाद के चक्कर में सदस्य बनाए गए और प्रेस क्लब की सदस्यता के नाम पर सीधे कुकर्मों और वसूली में संलग्न हैं।

म.प्र. शासन से हमारी सीधी मांग है कि इंदौर प्रेस क्लब में इंदौर के सभी पत्रकार जो साप्ताहिक दैनिक समाचार पत्रों में विशुद्ध लेखन कार्य में संलग्न हैं, उन्हीं को मात्र इंदौर प्रेस क्लब में सदस्य बनाया जाए। साथ ही यदि वर्तमान कार्यकारिणी यदि मात्र दैनिक समाचार पत्रों में लेखन कार्य में संलग्न व्यक्तियों को ही सदस्य रखती है तो उसे इंदौर दैनिक समाचार पत्र पत्रकार प्रेस क्लब में परिवर्तित किया जाए।

(पेज 1 का शेष)

जनता अमेरिका की भी बिहार जैसी.....

जिस अमेरिकी जनता को उसने 4 वर्षों में बेरोजगारी, अमेरिकी सैनिकों की आए दिन अफगान और ईराक में मौतें, पूरी दुनिया में उसकी दादागिरी दिखाने की नियत से होने वाली थू-थू, गिरती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डालर की कीमतें, संयुक्त राष्ट्र की लताड़ के बाद भी अमेरिकी जनता ने बुश को चुन लिया। नि:संदेह अंतिमसमय में बुश के इशारे पर खेला गया पाकिस्तानी सैन्य शासक मुशर्रफ का ओसामा का टेप करिश्मा दिखा गया और इस जालसाजी के लपेटे में अमेरिकी जनता ने बुश को चुन कर दिखा दिया कि वह भी उतनी ही मूर्ख, जज्बाती और निकम्मी है जितनी भारत क़ी औररुसके बिहार की जनता।

अब जबकि बुश चुन कर आ ही गया है अर्थात अगले 4 वर्ष दुनिया में भीषण रक्तपात किसी भी बहाने किसी भी देश में किया जा सकेगा, चाहे उसके लिए कोई ठोस आधार हो या नहीं। दुनिया के 85 से ज्यादा देशों में पड़ी अमेरिकी सेना अब कभी भी, किसी भी पल करवट बदलकर जो भी दुनिया का देश उसे नहीं मानेगा जानेगा उस पर 24 घंटे के अंदर निशाना बना दिया जाएगा।

नि:संदेह अमेरिक राष्ट्रपति भी संयुक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों,हथियार उत्पादकों की कठपुतली बन नाचता है। ये कंपनियां जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। दुनिया में जो राष्ट्र इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों, हथियार उत्पादकों की बात नहीं मानेगा ये धूर्त गिद्ध उस पर आक्रमण करने का बहाना ढूंढ कर चाहे वो झूठा ही क्यों न हो आक्रमण कर उस देश को अपना गुलाम बना कर वहां की औरतों से वैश्यावृत्ति करवाएगा और आदमियों को जो नहीं मानेगा उसे जेल में सड़ाएगा या गोलियों से उड़ा देगा। जैसा कि ईराक और अफगानिस्तान की कहानी को दुनिया देख रही है। बुश दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी लुटेरा सफेद पोश अपराधी है, जिसे अमेरिका की जनता ही हराकर दंड दे सकती थी, परन्तु अंतिम समय में खेले नाटक में उलझकर उसने पुन: अपना आका चुन दुनिया की बर्बादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अगले 4 वर्षों में दुनिया की क्या तस्वीर बदलेगी यह स्वयं विश्व की जनता जो जीवित रहेगी, देखेगी और भोगेगी। हाल-फिलहाल तो पेट्रोल, गैस और मिट्टी के तेल की कीमतों से लड़ाई लड़ेंगे।

(पेज 4का शे,)

आखिर क्यों म.सा.ब्र.

होते हैं। सभी गैंगस्टर, तो वो सदस्यों को फायदा के लिए नहीं सदस्यों को लूटने को उस पर अजगर की तरह कुंडली मार गुंडागर्दी से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सचिव और संचालक बने रहते हैं। उनके चुनावों की सारी घालमेल कहानी होती है। उन जालसाजों को ये हरामखोर जिनको ये रोटी के टुकड़े डालते हैं वहां बैठे संयुक्त संचालक, सहायक संचालक, अंकेक्षण, सहायक संचालक पंजीयन से लेकर नीचे चपरासी तक जालसाजियों और नियम विरुद्ध कुकर्मों में सहयोग देते हैं।

वैसे भी बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री को चाहिए कोई भी सहकारिता का पदाधिकारी व उसके परिवार का अन्य सदस्य उसी पद पर अगले चुनाव तक नहीं बैठेगा। इससे चुनावों में न केवल अन्य सदस्यों को अवसर मिलेगा वरन भ्रष्टाचार भी रुकेगा। इंदौर में कार्यरत लगभग 3000 सहकारी संस्थाओं में चारों तरफ यही हाल है।

(पेज 1 का शेष)

नई बोतल में पुरानी शराब....

उठाकर या राज्य शासन के खाद्य निगमों से उठाकर हरामखोर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो आई.ए.एस. ही होता है. सरपंचों को आवंटन दिखाकर या सरपंचों को आवंटित कर अधिकांस गेंहू, आटा, मैदा और सजी मिलों को बाले-बाले ही पैसा हजम कर लिया जाता है. वर्तमान कठपुतली प्रधानमंत्री मनमोहन जो सोनिया और उसकी चांडाल चौकड़ी के इशारे पर नृत्य करते हैं, ने उसी योजना को पुर्नउद्घाटित करने की अपेक्षा उस योजना के ठोस क्रियान्वयन की तरफ ध्यान देना था ताकि ग्रामीणों को सचमुच कार्य दिवस उपलब्ध करवाकर अन्न का वितरण सुनिश्चित किया जाता पर ध्यान नहीं दिया, मीडिया में स्थान बनाने की नौटंकी अवश्य पूरी की।

(पेज 1 का शेष)

शत्रु तांडव करे, सत्ताधीश मजे.....

अधिकांश आतंकवादी संगठनों को कांग्रेसी अशासकीय संगठनों के माध्यम सेभी धन उपलब्ध करवाते हैं, फिर उसीके हिस्सेदारी में से धन खाते हैं। ये पूरे उत्तरी पूर्वी भारत की कहानी है। अशासकीय संगठनों द्वारा धन शासन के साथ जनता से भी वसूली की जाती है। उसी धन से आतंकवादी गतिविधियों का चलाना आतंकवादियों को धन हथियार और प्रचार सामग्री उपलब्ध करवाने में ये शासन के धन से चलने वाले अशासकीय संगठन भारी भूमिका अदा करते हैं। अधिकांश आतंकवादी संगठन किसी न किसी नेता की पैदाइश होते हैं और उसकी कमाई का स्त्रोत भी। यदा-कदा पकड़े भी जाते हैं, परन्तु सबूतों के अभाव में आराम से बरी हो जाते हैं। जबकि इन आतंकवादी संगठनों को पूरे जम्मू कश्मीर में उत्तरी पूर्वी भारत में पुलिस का संरक्षण भी मिला होता है। आतंकवादी संगठनों में अहं भूमिका अदा कर एक दूसरे को संभाल कर चल रहे हैं। 1980 के दशक से। इसलिए न तो आतंकवादियों का सफाया हो सकता है और न ही पूरी पुलिस में बदलाव। कश्मीर के पुलिस अधिकारियों को तो आई.एस.आई. से भी पैसा मिलता है जो कई बार पकड़े जा चुके हैं। इसलिए वो आसानी सीमा सुरक्षा बलों, थल सेना की टुकड़ियों पर भी आक्रमण करने में सफल हो जाते हैं। नि:संदेह थल सेना के अधिकारी भी जानबूझकर आतंकवादियों के धन का उपयोग कर अपने ही सैनिकों को मरवाने से भी नहीं चूकते। जैसा कि कई बार कश्मीर में हो चुका है।

इतनी सारी अव्यवस्थाओं के रहते भारतीय राजनीति के शिखर पद पर बैठे राजनीतिज्ञों को कोई ठोस नीति नहीं मिल रही जो इन सब आतंकवादियों को समाप्त कर सके या उनके हथियार डलवा सके। जो कि दीर्घकालीन शांति स्थापित कर सके क्योंकि उन्हें धन कमाने और मौज मस्ती और सत्ता का सुख भोगने से फुर्सत ही नहीं मिल पा रही। अधिकारियों, सचिवों को देश की नहीं अपनी विदेश यात्राओं, सत्ता में रहते धन बटोरने से समय मिले तो वो जलते देश को कुछ अच्छा और ठोस दे सकें।

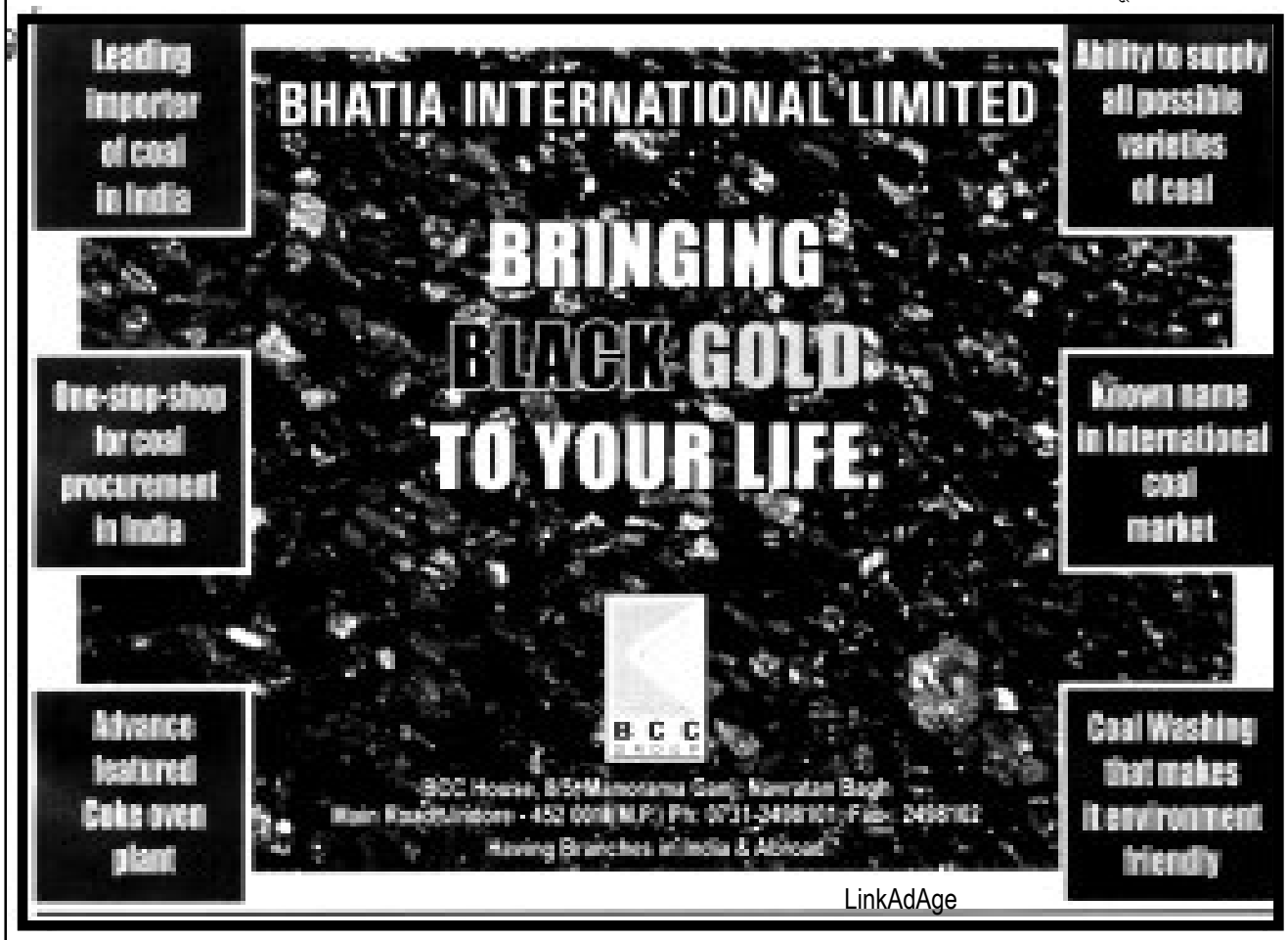

परिवहन में अवैध वसूली पर गिरी गाज

किराये के नोट गिनने वाले वाले बोरों में भरते थे नोट

म.प्र. परिवहन विभाग का प्लाइंग सकाड रास्ते में चेकिंग कर कागज देखने के नाम पर बोरों से अवैध वसूली करता था। उन नोटों को गिनने के लिए नोट गिनने वाले कर्मचारी बाहर के होते थे। लोकायुक्त छापा न मार दे इसलिए वो दलाल भी अलग से रखे जाते थे। अचानक मुख्यमंत्री ने अवैध वसूली का ये कारोबार झटके में समाप्त कर दिया। दूसरी बिजली गिरी एकल खिड़की प्रणाली से, कर्मचारियों को जो हर दस्तखत पर अलग से नोट मिलते थे उस पर भी अंकुश लगने का प्रयास किया।

नि:संदेह दलाल अभी भी सक्रिय हैं सभी वैध-अवैध कार्यों में चाहे फिर वह चालक अनुज्ञप्ति या बसों के वैध-अवैध परमिट का सौदा। आर.टी.ओ. रघुवंशी के आने से ढर्रे में सुधार को आया है, पर पूरी तरह नहीं। रिश्वत का खेल अभी भी जोरों पर है।

म.प्र. शासन में मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के बनते ही प्रशासनिक दुरुस्ती का सिलसिला शुरू तो हुआ है। परन्तु हरामखोर महाभ्रष्ट अर्जुनसिंग की चरणदासी जो वर्तमान मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं जबकि वो दो तिहाई भाजपा बहुमत के मुख्यमंत्री हैं। इस पर भी उस गिद्ध की कोप दृष्टि अभी भी म.प्र. पर है। उसके द्वारा अपने मोहरों को सेट करने की कारस्तानी बंद नहीं हुई है। यही कारण है कि बाबूलाल गौर जैसा पेशे से वकील मुख्यमंत्री भी खुलकर कार्यशील नहीं हो पा रहे हैं। इसी सुधार प्रक्रिया में महाभ्रष्ट विभागों की श्रेणी में गिने जाने वाले आर.टी.ओ. में भी सुधार लाने के प्रयासों में पहला म.प्र. के आर.टी.ओ. का फ्लाइंग स्काड को अचानक बंद करना और दूसरी एकल खिड़की प्रणाली लागू करना मुख्य है। परन्तु निष्कर्ष में क्या इतना महाभ्रष्ट विभाग सचमुच सुधर गया, नहीं पूरा तो नहीं परन्तु परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। नि:संदेह एकल खिड़की प्रणाली पर सारे संबंधित कार्य के कागजात ढाई बजे तक लिए जाते हैं। उसके बाद खिड़की बंद करने का प्रावधान बताया गया। इसके विपरीत हमारी कैमरा टीम ने खिड़की को 7-10-2004 को 2 : 10 बजे ही बंद पाया।

दलालों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि इस एकल खिड़की की प्रणाली पर सच ये है कि चूंकि इसके बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार न किए जाने से एक तो जनता को नहीं मालूम, दूसरा दलालों की भी इससे रोजी-रोटी पर असर तो पड़ा है। नि:संदेह समय सीमा में कार्य करने के प्रयास विभागीय स्तर पर शुरू हो चुके हैं। इसके विपरीत पूरे प्रदेश में कम से कम 3000 से ज्यादा बसें जो बिना परमिट या अवैध परमिट की दौड़ रही हैं। उनमें कोई परिवर्तन अभी तक देखने में नहीं आया अर्थात प्राथमिक स्तर पर सुधार हुआ है, परन्तु द्वितीयक स्तर पर लेने देने के सिलसिले में परिवर्तन 10-20 कर्मचारियों सहायक निरीक्षकों के निलंबन के अतिरिक्त आ भी नहीं सकता क्योंकि अधिकांश बसें बिना परमिट की या अवैध परमिट की अधिकांश पुलिस, आर.टी.ओ., प्रशासनिक अधिकारियों और सत्ताधीश नेताओं या कांग्रेसी नेताओं की ही चल रही है। मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की इतनी औकात भी नहीं कि इन नेतों, पुलिस अधिकारियों और आर.टी.ओ. वालों की बसों, ट्रकों, टैंकरों को जो बिना वैध परमिट और कर चुकाए बिना भी न दौड़े सब ही जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री की कितनी औकात है। 5 वर्ष उसके बाद और पहले भी इन प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस व आर.टी.ओ. के अधिकारियों को तो 25 से 35 साल शासन में बैठकर ही न केवल भ्रष्टाचार कर वसूली करना है वरन ऐसे कई मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों को भी सत्ता में रहते तक ही सलाम ठोंकना है उसकी सत्ता के पहले सत्ता के बाद इनकी कोई औकात बख्त नहीं रह जाएगी। नि:संदेह रघुवंशी भी इस दो नं. के अवैध व बिना परमिट की बसों को सड़क पर चलाने का धन तो वसूल कर हिस्सेदारी कर ही रहे हैं। भले ही वो कितने दूध के धुले बनें। भोपाल प्रतिनिधि के अनुसार अब अवैध परमिट ही गाड़ियां भाजपा नेताओं की ही चलेंगी या पुलिसिये अधिकारियों की। इसके अतिरिक्त किसी को चलाना हो तो सीधे मंत्रालय से संपर्क कर धन खर्च करे। नि:संदेह वोटों से नोट वसूली बंद होने से परिवहन विभाग में वसूली का माहौल है।

ताई ने स्वयं छवि बिगाड़ी

श्रीमती सुमित्रा माजन वरिष्ठ भाजपा नेत्राणी और हेट्रिक वाली सांसद ने अंजु माखीजा को महापौर बनाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, फिर भी असफलता हाथ लगी। नि:संदेह अंजु और चंदू माखीजा ही तो थे, जिन्होंने सांसद निधि के रु. 10 करोड़ पिछले 5 वर्षों में ठिकाने लगाए, ये वही चंदू माखीजा हैं जिन्होंने प्रधान मंत्री सड़क योजना में ठेके तो सांसद के माध्यम से बहुत लिए, परन्तु की सड़कें अभी तक नहीं बनी। बरसात में उन प्रधान मंत्री सड़क योजना की सड़कों की हालत देखने लायक हो जाती है। फिर बैंक का ऋण लेकर पी जाना तो ठेकेदारों का प्रथम कर्त्तव्य होता है फिर चंदू की अंजू माखीजा तो सांसद की भी कोषाध्यक्ष थीं। अधिकांश सांसद निधि के ठेकेंजु के माध्यम से चंदू को ही मिलते थे। यदि सीबीआई जांच करे या करवाई जावे तो उल्टे ही सांसद निधि की बंदरबाट के मामले में चंदू और अंजू की जालसाजियों का परिणाम उल्टे ही श्रीमती महाजन के गले में पड़ जाएगा। अनेकों सड़कों के काम जो चंदू माखीजा की ठेकेदारी में थी न केवल अधूरे हैं और स्तरहीन सड़कों के निर्माण के बाद भी सांसद के दबाव में भुगतान कर दिए गे। ऐसे ही एक सड़क चापड़ा के रा.रा. 59 ए के अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर से जोड़ी जानी थी। 5 कि.मी. की सड़क की हमारे पास वीडियो शूटिंग मार्च 2004 की है। सन 2002 से बनने वाली सड़क मार्च 2004 तक भी पूरी नहीं हुई थी और ये भुगतान कार्य से ज्यादा ले लिए गए थे. इतनी जालसाजियों के बाद भी अंजू माखीजा की इतनी तरफदारी कर सुमित्रा महाजन ने न केवल अपनी छवि को स्थानीय स्तर पर वरन राष्ट्रीय स्तर पर भी गिरवा लिया। नि:संदेह उमा शशि का महापौर के रूप में सदुपयोग पुरानी चांडाल चौकड़ी ही अपने हितों में अपनी तरह से करने के लिए ही करेगी। परन्तु जिसकी लड़ाई एक सम्मानीय सांसद ने की वह तो निंदनीय ही थी।

जांच के बहाने दीवाली की वसूली

इंदौर। वाणिज्य कर का मुख्यालय में बैठे भ्रष्ट आयुक्त से लेकर उपायुक्त, सहायक आयुक्त अपनी वसूली के लिए कैसे गुल खिलाते हैं। इसका नमूना पाठक पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी पिछले तीन-चार माह से चलने वाला ट्रकों और बसों को रोककर वसूली का अभियान सिद्ध करता है। बसों में बिना लि के मोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स का सामान पकड़ा जाता है। ट्रकों में काजू, छुआरे, किशमिश या महंगा सामान पकड़ा जाता है। सारे सहायक आयुक्त को भ्रष्ट लुटेरे उपायुक्त बघेल,, एस.एल. वर्मा और आर.सी. पालीवाल को कमाई कर देते हैं। उन्हीं को जाचं कार्य और पकड़ा धकड़ी पर लगाया जाता है।

इसकी जांच की आड़ में पूरे म.प्र. में सहायक आयुक्तों और उनके चेलों सहायक वाणिज्य कर अधिकारी मिलकर पिछले 4 महीने से ट्रकों और बसों को बीच बाजार में घेरकर आए दिन वसूली कर रहे हैं। ये इन हरामखोर सहायक आयुक्तों के हौंसले कितने बुलंद हैं, कि यदि कोई पत्रकार इनकी इन कारगुजारियों की पूछताछ करता है तो इन धूर्तों की टोली उन्हें अपने यहां कार्यरत नशे में धुत रहने वाले चपरासियों से कहकर हाथापाई तक करवाते हैं। इनकी शिकायत वाणिज्य औरउद्योग मंत्री से करने के बाद भी इनकी लूट और अवैध वसूलियां बंद नहीं हुई हैं।

स्वाभाविक है भ्रष्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्री कैलाश चावला भी इन अवैध वसूलियों में हिस्सेदार हैं। जबकि दमखम वाले व्यापारी इनकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और कैलाश चावला से भी कर देते हैं। इसके बावजूद इनका धर पकड़ अभियान केवल वसूली कर छोड़े तक सीमित हो गया है। पढ़िये अगले अंकों में कैसे चेतक चेंबर के वाणिज्य कर के सहा. आयुक्तों की टोलियां, मांगलिया, लोहा मंडी, सियागंज, ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक रोककर कैसे वसूलियां कर रही हैं।